



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2001/अग्रहायण 16, 1923

No. 326]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2001/AGRAHAYANA 16, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2001

प्रारंभिक जांच परिणाम

विषय : यू.के., जर्मनी, ब्राजील और बुल्गारिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयातों में संबंधित पाटनरोधी जांच—प्रारंभिक जांच परिणाम

सं. 32/1/2001-डीजीएडी.— भारत सरकार, 1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,

1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. प्रक्रिया

2. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:-

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) को नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से एक्रिलिक फाइबर विनिर्माता फोरम से एक लिखित याचिका प्राप्त हुई, जिसमें यू.के., जर्मनी, ब्राजील और बुल्गारिया (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है ।

(ii) भारत में एक्रिलिक फाइबर के निम्नलिखित उत्पादकों और फॉर्म के मद्दम्यों (जिन्हें एतदुपपन्न याचिकाकर्ता कहा गया है) ने पाटनरोधी जांचों में भाग लेने के लिए विशेष तौर पर सहमति व्यक्त की है -

- क) मै0 इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड, जिसका कार्यालय एस सी ओ, 49-50, सेक्टर 26, चंडीगढ़ में स्थित है।
- ख) मै0 कंसोलिडेटेड फाइबर एण्ड कैमिकल्स लि0, जिसका कार्यालय, 97, पार्क स्ट्रीट तृतीय, कोलकाता में स्थित है।
- ग) मै0 पशुपति एक्रिलोन लिमिटेड, जिसका कार्यालय एम-14, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है।

दो अन्य घरेलू उत्पादकों, अर्थात् मै0 इंडियन पेट्रोकेमिकल्स एंड कैमिकल्स लि0, बड़ौदा ; और मै0 वर्धमान एक्रिलिक्स लि0, लुधियाना ने याचिका का समर्थन किया है।

(iii) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए पाटन संबंधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत स्थित यू.के., जर्मनी, ब्राजील और बुल्गारिया के दूतावासों को सूचना दी।

(iv) प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष 5501.30 तथा 5503.30 के अंतर्गत आने वाले एक्रिलिक फाइबर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी की कार्रवाई शुरू करते हुए दिनांक 28 अगस्त, 2001 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

(v) प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, उद्योग एसोसिएशनों और शिकायतकर्ताओं को उक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी तथा उन्हें अपने विचार लिखित रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।

(vi) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 6 के उपनियम (3) के अनुसार सभी ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को याचिका की प्रति उपलब्ध करवाई।

(vii) प्राधिकारी ने निम्नलिखित निर्यातकों को संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रश्नावली भेजी।

1. अकोरडिस ए जी
कासिनोस्ट्रासे 19,
42103, वुप्परटाल
जर्मनी ।
2. वेयर फेसर जीएमबीएच
41538, डोरभाजन
जेसेलसेफन, फेसरवर्क लिंजन
जी वी डब्ल्यू जर्नवरड लिंग्स वर्क जीएमबीएच गोच
जर्मनी ।
3. मार्किशे फेसर ए जी,
पार्करस्ट्रासे
14727 प्रेमनिटज
जर्मनी
4. डयू पोंट डिय नेमरस (डचलैड)
डयू पोंट स्ट्रासे
61 352 वाड होमवर्ग वी.डी.
जर्मनी ।
5. अकोरडिस
वेरटकोट सैंट स्ट्रीट
ब्राडफोर्ड
यू.के.
6. नेफ्टोरियम पेटोकैमिकल कंप्लैक्स
ऑर्गानिक फाउंडर कंप्लैक्स,
वरगास
बुलगारिया ।
7. रोडिया ब्रेसिल क्रिलर
एक्रिलिक फाइबर डिवीजन

सेन्ट्रो इम्प्रेसरियल ए वी मारिया

कोल्हो अगुइयर 215,

ब्लाक बी, सीईपी05804-902,

साओ पोला,

ब्राजील

(viii) नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को भी जांच शुरू करने के बारे में सूचित किया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें ।

(ix) संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उपयोक्तोओं/आयातकों एसोसिएशनों को प्रश्नावली भेजी गई थी:-

मै0 राजस्थान स्पिनिंग एंड बीबिंग मिल्स लि0,

भीलवाडा, भवन,

40 कम्युनिटी सेन्टर,

नई दिल्ली-110065

मै0 सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्स लि0,

211, गनन दीप,

12, राजेन्द्रा प्लेस,

नई दिल्ली - 110008

मै0 आदिनाथ टेक्सटाइल्स लि0,

गाँव - भोलापुर

पो0आ0 साहबाना मुंडिया,

लुधियाना,

पंजाब ।

मै0 वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स

चंडीगढ़ रोड,

लुधियाना - 1410011

पंजाब ।

मै० मालवा काटन स्पिनिंग मिल्स लि०,

इंडस्ट्रियल एरिया " एँ

लुधियाना-141003

पंजाब

मै० विनसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि०,

एस सी ओ 144-145, सेक्टर 34-ए

चंडीगढ़-160022

मै० भिवानी टेक्सटाइल मिल्स,

भिवानी (जिला- हिसार)

हरियाणा ।

मै० श्रुति सिंथेटिक्स लि०,

गाँव लोयार गगुंडा रोड़,

उदयपुर,

राजस्थान ।

मै० नाहर स्पिनिंग मिल्स लि०,

373, इंडस्ट्रियल एरिया-ए

लुधियाना-141003

पंजाब ।

इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन,

मार्फत दि मिलआनर्स एसोसिएशन,

एल्फिन स्टोन बिल्डिंग,

10, वी नरीमन रोड़,

फोर्ट, मंबई-400 001

(x) याचिकाकर्ताओं से क्षति से संबंधित अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी वह प्रस्तुत भी कर दी गई थी ।

(xi) प्राधिकारी ने उसके द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा ।

(xii) ***** यह चिह्न इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का द्योतक है और नियमों के तहत प्राधिकारी ने इसे ऐसा ही माना है ।

(xiii) इस जांच में 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक की अवधि शामिल है ।

(xiv) जांच शुरू करने संबंधी सूचना की प्रतियां व्यापक परिचालन हेतु फिक्की, सी आई आई, एशोचेम इत्यादि को भी भेजी गई थीं ।

ख. याचिकाकर्ता के विचार

3. याचिकाकर्ताओं ने अपने अनुरोधों में निम्नलिखित मुख्य तर्क दिए हैं-

- i. वर्तमान याचिका में जांचाधीन उत्पाद एक्रिलिक फाइबर है ।
- ii. एक्रिलिक फाइबर सिन्थेटिक पोलिमर की एक लम्बी श्रृंखला होती है जिसमें एक्रिलोनाइट्राइल यूनिटों का भार कम से कम 90 % होता है । एक्रिलिक फाइबर एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टो अथवा एक्रिलिक टॉप हो सकता है । एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टो और एक्रिलिक टॉप ए सभी एक्रिलिक फाइबर के रूप में जाने जाते हैं । एक्रिलिक फाइबर और एक्रिलिक टो में केवल लम्बाई की भिन्नता होती है । एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन विभिन्न ग्रेडों में किया जाता है, जिन्हें इसके डेनियर के रूप में परिभाषित किया जाता है । एक्रिलिक फाइबर कीमती ऊन के लिए एक किफायती प्रतिस्थपक है । एक्रिलिक फाइबर का इस्तेमाल मानव के दैनिक उपयोग में किया जाता है। एक्रिलिक फाइबर का परिधान, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रयोग किया जा सकता है ।

- iii. एकिलिक फाइबर (जिसमें टो, टॉप और स्टेपल शामिल हैं) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 55 के उपशीर्ष संख्या 5501.30 और 5503.30 के अंतर्गत वर्गीकृत है ।
- iv. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित एकिलिक फाइबर और संबद्ध देशों से निर्यातित एकिलिक फाइबर में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित एकिलिक फाइबर में भौतिक और रासायनिक, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में समानता है । इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एकिलिक फाइबर को उक्त नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जाना चाहिए ।
- v. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि एकिलिक फाइबर के घरेलू उत्पादन में उनका एक बड़ा हिस्सा बनता है ।
- vi. जहां तक यू.के. के मामले में सामान्य मूल्य का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने यू.के. में घरेलू बिक्री के साक्ष्य के आधार पर इसका दावा किया है । याचिकाकर्ता ने यू.के. में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बीएटी और विदेशी मोड के लिए समायोजन किया है । जहां तक जर्मनी में सामान्य मूल्य का संबंध है, याचिकाकर्ता जर्मनी में घरेलू बिक्रियों का कोई साक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है । उन्होंने जर्मनी के उत्पादक द्वारा तीसरे देश को किए गए संबद्ध वस्तु के घरेलू निर्यात के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । उन्होंने स्वदेशी भाड़े के बारे में समायोजन करने के पश्चात् तीसरे देश को निर्यात की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है । जहां तक ब्राजील एवं बुल्गारिया का संबंध है, याचिकाकर्ता इन देशों में घरेलू बिक्रियों अथवा तीसरे देश को हुए किसी निर्यात का साक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है । उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रकाशित कीमतों के आधार पर प्रमुख कच्ची सामग्री एकिलोनाइट्राइल की कीमत को हिसाब में लेने के बाद परिकलित उत्पाद लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

- vii) याचिकाकर्ताओं ने डीजीसीआई एण्ड एस कोलकाता द्वारा प्रकाशित आकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, निर्यात के देश में घरेलू परिवहन और पत्तन हैंडलिंग प्रभारों के संबंध में भारित औसत सीआईएफ निर्यात कीमत में से समायोजन किए हैं।
- viii) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस याचिका से पहले, घरेलू उद्योग का विभिन्न देशों से हुए एक्रिलिक फाइबर के पाटन से क्षति हो रही थी और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूएसए, थाईलैंड, कोरिया जनगण, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, जापान, मेक्सिका, तुर्की तथा तड़वान से एक्रिलिक फाइबर के आयातों के संबंध में जांच शुरू की है। स्पष्टतः घरेलू उद्योग को एक के बाद एक विभिन्न स्रोतों से हो रहे पाटन के कारण नियमित रूप से क्षति हो रही है।
- ix) यूके, जर्मनी, ब्राजील तथा बुल्गारिया के निर्यातक भारत में एक्रिलिक फाइबर का पाटन कर रहे हैं और निर्दिष्ट प्राधिकारी विभिन्न स्रोतों से इन पाटित आयातों के सचयी प्रभाव की जांच कर सकता है जैसाकि पाटनरोधी नियमों के तहत अपेक्षित है।
- x) प्रत्येक संबद्ध देश से हुए आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- xi) संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- xii) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में कमी आई है।
- xiii) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है। तथापि, उद्योग विभिन्न स्रोतों से हानि वाले आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी उचित कीमत प्राप्त नहीं कर पाया है क्योंकि नए स्रोतों से आयात हानि शुरू हो गए हैं।
- xiv) 2000-01 के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में 17 % से अधिक की कमी आई है जा कि सीधे तौर पर कुछ ग्राहकों का पाटित आयातों की ओर झुकाव के कारण हुआ है।

- xv) हालांकि याचिकाकर्ता कम्पनियों के रोजगार स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है तथापि, यदि ऐसे हालात चलते रहते हैं तो घरेलू उद्योग को उत्पादन रोकना/बंद करना पड़ेगा जिसका रोजगार पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।
- xvi) उत्पादन लागत तथा उचित बिक्री कीमत से काफी कम कीमतों पर एक्रिलिक फाइबर की बिक्रियों से घरेलू उद्योग को भारी घाटा हुआ है । एक के बाद एक स्रोत से निरंतर पाटन होने से घरेलू उद्योग को ऐसी कीमत पर उत्पाद बचन के लिए मजबूर होना पड़ा है जिससे पूरी उत्पादन लागत भी प्राप्त नहीं हो पाती है ।
- xvii) घरेलू उद्योग को क्षति सीधे तौर पर संबद्ध दशों से पाटित आयातों के कारण हो रही है ।

(ग) निर्यातकों, आयातकों, उपयोक्ताओं एवं अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

4 निम्नलिखित निर्यातकों और निर्यातक संगठना से उत्तर प्राप्त हुए हैं :

- i) एकोरडिस यूके लि०, यूके
- ii) मै० लूकॉयल ऑयल कम्पनी, बुल्गारिया
- iii) डयूपोट डक्केंड होल्डिंग जीएमबीएच एंड कम्पनी क जी, जर्मनी
- iv) झालान जीएमबीएच बेयरवेर्क, जर्मनी
- v) इटरनेशनल रयान एंड सिंथेटिक फाइबरस कं० (सीआईआरएफएस), ब्रुसेल्स

5 उपरोक्त कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध तथा/अथवा उपलब्ध करवाई गई सूचना निम्नानुसार हैं:-

i) एकोरडिस यूके लि०, यूके

अपने उत्तर में मै० एकोरडिस ने भारत के घरेलू एक्रिलिक फाइबर उद्योग के साथ परामर्श करके ऐसी कीमत पर एक्रिलिक फाइबर का निर्यात न करने हेतु कीमत संबंधी वचन-पत्र का प्रस्ताव किया है जो घरेलू उद्योग के लिए क्षति कारक है :

ii) मै0 लूकॉयल कम्पनी, बुल्गारिया

मै0 लूकॉयल कम्पनी ने जांच की अवधि के दौरान तथा वर्ष 1998 और 1999 में भारत को किए गए निर्यातों अन्य देशों को किए गए निर्यातों की कुल मात्रा और मूल्य, घरेलू बिक्रियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है। कम्पनी के अनुसार, एक्रिलिक फाइबर की बिक्री भारत में एक एजेंट के जरिए यूके में पंजीकृत एक कम्पनी के द्वारा की गयी थी। घरेलू बाजार की बिक्री कीमतों में लगभग 3 % वित्तपोषण की लागत शामिल है क्योंकि बिक्री की शर्त सामान्यतः 90-120 दिनों के आस्थगित कीमत की होती है और सामान्य ब्याज दर 12 % वार्षिक के आस-पास होती है। निर्यातक ने परिशिष्ट-1 से 10 के साथ निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार पूर्ण उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

iii) डयूपॉट डचलैंड होल्डिंग जीएमबीएच एंड कम्पनी के जी, जर्मनी

मै0 डयूपॉट ने सूचित किया है कि वर्तमान में एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन और जर्मनी से भारत का इसका निर्यात नहीं कर रहे हैं। जून, 1990 में लिए गए एक निर्णय के पश्चात मूल कम्पनी तथा इसकी संबद्ध इकाइयों ने 1990 के दशक की शुरुआत में एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन बंद कर दिया है। इसलिए, उन्होंने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।

iv) ड्रालोन जीएमबीएच बेयरवर्क, जर्मनी

मै0 ड्रालोन जीएमबीएच ने सूचित किया है कि वे बेयर फासर जीएमबीएच बिजनेस यूनिट सक्रिलिक फाइबर्स के विधिक उत्तराधिकारी हैं। जिसकी स्थापना 1 जूनवरी, 2001 को की गयी थी। अप्रैल, 2000 मार्च, 2001 के दौरान उनकी कम्पनी के निर्यात 994 मी.टन के हुए थे। पिछले बारह महीने की अवधि के दौरान उनकी कम्पनी के निर्यात 1337 मी0 टन के हुए थे और इस प्रकार जांच अवधि के दौरान भारत के साथ उनके कारोबार में मात्रा रूप में 26% की कमी आई है। भारत में लगभग 1,20,000 टन वार्षिक की मिल खपत की तुलना में जांच अवधि के दौरान उनका बाजार हिस्सा लगभग 0.8% था और इस बाजार हिस्से के साथ वे भारतीय घरेलू उत्पादकों (न्यूनतम सीमा संबंधी नियमों के अनुसार) के लिए कोई खतरा नहीं पाते हैं। उनके अनुसार जांच अवधि के दौरान भारतीय घरेलू एक्रिलिक फाइबर उत्पादकों की लगभग 93-94 % की उपयोगता दर वह निष्पादन दर्शाती है जो कि समूचे विश्व के उद्योग की औसत के बराबर अथवा उससे अधिक है। उन्होंने अनुरोध किया कि ड्रालोन के विरुद्ध पाटनरोध शिकायत का निरस्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे इसे निर्मूल मानते हैं। तथापि, उन्होंने पूर्ण सूचना प्रस्तुत नहीं की है जैसाकि उन्हें भजी गई प्रश्नावली की परिशिष्ट-1 से 10 के तहत अपेक्षित है।

v) इंटरनेशनल रेयॉन एंड सिंथेटिक फाइबर्स कमेटी (सीआईआरएफएस), ब्रुसेल्स

इस एशोसिएशन के अनुसार सीआईआरएफएस, यूरोपीय मैन-मेड फाइबर उद्योग की प्रतिनिधि एसोसिएशन है। सीआईआरएफएस ने ई-मेल के जरिए भेजे गए अपने पत्र में निम्नलिखित प्रमुख तर्क दिए हैं :-

• बाजार हिस्सा

यू0के0 तथा जर्मनी से हुए आयातों का भारत में बाजार हिस्सा काफी कम स्तर पर रहा है। जर्मनी के मामले में, 2000-2001 में बाजार हिस्सा (एक्रिलिक फाइबर मैन्यूफैक्चर्स फारम द्वारा दायर याचिका में दी गई सूचना का प्रयोग करते हुए) केवल 1.7% और यूके संबंध में 1.1% माना जा सकता है। सीआईआरएफएस का यह तर्क है कि भारतीय एक्रिलिक फाइबर बाजार की परिस्थितियों में यह बाजार हिस्सा भारतीय उत्पादकों की क्षति पहुँचाने के लिए काफी कम है।

• यू0के0 तथा जर्मनी में सामान्य मूल्य

याचिका में निहित यूके तथा जर्मनी में सामान्य मूल्य का आकलन अत्यधिक भ्रामक है। विशेषज्ञ परामर्शदाताओं से प्राप्त सूचना अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 में पश्चिम यूरोपीय बाजार में 1.33 डॉलर के भारत औसत सहित 1.20 डॉलर से 1.45 डॉलर प्रति किग्रा के बीच बिक्री कीमतों का अनुमान दर्शाती है। अतः याचिकाकर्ताओं द्वारा जर्मनी में 1.66 डॉलर तथा यूके में 2.67 डॉलर के सामान्य मूल्य का आकलन स्पष्ट तौर पर विशिष्ट उत्पादों के आधार पर किया गया है, जो कि उनके साथ तुलनीय नहीं हैं जिनका आमतौर पर भारत का निर्यात किया जाता है। इसलिए परामर्शदाताओं की रिपोर्ट में दिए गए साक्ष्य को जर्मनी, यूके में सामान्य मूल्य के उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि सबद्ध परामर्शदाता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। तथापि परामर्शदाता की उक्त रिपोर्ट प्राधिकारी का प्राप्त नहीं हुई है।

सीआईआरएफएस के अनुसार घरेलू उद्योग का हुई क्षति के वास्तविक कारण ये हैं।

(क) अपर्याप्त आकार

याचिकाकर्ताओं के संयंत्रों का औसत आकार 24,000 टन के औसत सहित 12,000 टन से 38,500 टन के बीच है। यह एक्रिलिक फाइबर उत्पादन इकाई को सक्षमता से चलाने के लिए आवश्यक लाभकारी आकार से काफी कम है।

यूके तथा जर्मनी में संयंत्र आकार 70,000 टन से लेकर 150,000 टन के बीच हैं। विश्व में अन्यत्र कुछेक संयंत्रों का आकार 200,000 टन से भी अधिक है। याचिकाकर्ताओं का आयात से असंबद्ध गंभीर कठिनाईयों तक तक होती रहेंगी जब तक वे अलाभकारी आकार की इकाईयों चलाते रहेंगे।

(ख) अपर्याप्त प्रौद्योगिकी

कुछ भारतीय संयंत्र पुराने हैं, उनमें से कुछ कई वर्षों पहले आयातित पुराने और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अप्रचालित हैं। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन लागत ज्यादा है, गुणवत्ता भरोसे-मंद नहीं है और उत्पादक उत्पादों की प्रत्येक किस्म की आपूर्ति करने में असमर्थ हैं।

(ग) एक्रिलिक फाइबर उत्पादकों को अत्यधिक संरक्षण

भारतीय वस्त्र उद्योग (स्पिनिंग, विविंग, प्रसंस्कृत परिधानों का विनिर्माण तथा घरेलू वस्त्र) भारतीय जनता को उत्पादों का एक अनिवार्य आपूर्तिकर्ता और एक प्रमुख निर्यात क्षेत्र, दोनों है। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है, और भारत की निर्यात आय में बहुत बड़ा योगदान करता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाने से इसे गंभीर नुकसान हुआ है और यदि वर्तमान जांच का परिणाम आगे और पाटनरोधी शुल्क लगाना निकलता है तो इससे इस और भी नुकसान होगा।

सीआईआरएफएस ने आगे यह उल्लेख किया है कि:

- i) भारतीय एक्रिलिक फाइबर की कीमतें विश्व में सर्वाधिक कीमतों में से हैं।

परामर्शदाताओं की प्रमुख फर्म के अनुसार 2000/2001 में एशिया में एक्रिलिक फाइबर की कीमत का औसत 1.36 डॉलर प्रति कि०ग्रा० रहा है। यह लगभग 63 रुपये के बराबर है। याचिका में इसी अवधि में भारत में बिक्री कीमतों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गयी है।

- ii) भारतीय उत्पादकों ने विश्व के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कीमतों में तेजी से वृद्धि की है।

याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता की ~~विक्री~~ कीमतों में 1999-2000 तथा 2000-2001 के बीच 26.5 % तक की वृद्धि हुई। यह दर विश्व के अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि की दर से काफी अधिक है।

- iii) भारतीय वस्त्र उद्योग को अच्छी गुणवत्ता और उनके उत्पादों के मूल्य वर्धन के लिए आवश्यक अपेक्षाकृत अधिक नवीनतम फाइबर प्राप्त करने की मनाही की जाएगी।

यूके तथा जर्मनी में उत्पादक भारत में विनिर्मित न होने वाली कई फाइबर किस्मों सहित उच्चतम गुणवत्ता के फाइबर का उत्पादन करते हैं। इन मूल्य वर्धित उत्पादों से भारतीय स्पिनर्स, वीवर्स और निर्सर्स को अपने उत्पादों की गुणवत्ता तथा आकर्षण और उन कीमतों को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिन पर वे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्राप्त कर सकते हैं, यदि उन्हें मुक्त पहुँच की अनुमति दी जाती है।

अतः सीआईआरएफएस ने जर्मनी तथा यूके से संबंधित पाटनरोधी जांच को उसके डब्ल्यूटीओ करार के असंगत होने और उस गंभीर क्षति के आधार पर तुरंत बंद करने का अनुरोध किया है जा कि भारतीय वस्त्र उद्योग को एक्रिलिक फाइबर पर आग और पाटनरोधी कार्रवाई करने से पहुँचेगी।

6. निम्नलिखित आयातकों/एसोसिएशन ने उत्तर दिए हैं—
 मैसर्स ए पी एम इंडस्ट्रीज लि०, भिवाडी, राजस्थान
 मैसर्स दीपक स्पिनर्स लि०, चण्डीगढ़
 मैसर्स इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन, मुंबई

(i) मैसर्स ए पी एम इंडस्ट्रीज लि०, भिवाडी, राजस्थान

मै० ए पी एम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इटली और जापान से हुए अपने आयातों के बारे में सूचना दी है जो इन जांचों के संगत नहीं हैं ।

(ii) मैसर्स दीपक स्पिनर्स लि०, चण्डीगढ़

मैसर्स दीपक स्पिनर्स लि० ने प्रश्नावली का आंशिक उत्तर दिया है । संबद्ध देशों से हुए आयातों के संबंध में उन्होंने अग्रिम लाइसेंस (शुल्क मुक्त योजना) के अंतर्गत *** सी आई एफ, मुंबई की दर से जर्मनी से *** मात्रा के आयात के बारे में सूचना दी है । उन्होंने अनुबंध-4 में शुल्क के भुगतान के साथ संबद्ध वस्तु के कोई अन्य आयात नहीं दर्शाए हैं । उन्होंने अनुबंध-5,6 और 7 के संबद्ध में भी कोई सूचना नहीं दी है ।

(iii) मैसर्स इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन, मुंबई

इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन ने अपने उत्तर में निम्नलिखित प्रमुख तर्क दिए हैं—

- (क) यू के और जर्मनी से नगण्य आयात:

इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन के अनुसार एक्रिलिक फाइबर के आयात के आंकड़े निम्नानुसार हैं—

(मात्रा किग्रा में)

वर्ष	यू के	जर्मनी	ब्राजील	बुल्गारिया
1996-97	55,624	10,14,658	शून्य	शून्य
1997-98	3,56,056	5,88,861	6,585	शून्य
1998-99	18,521	8,56,765	25,334	शून्य
1999-2000	9,404	9,76,966	70,213	18,070
2000-2001 (अप्रैल से फरवरी)	94,074	11,11,224	शून्य	18,519

वर्ष 1997-98 के बाद यू के से एक्रिलिक फाइबर के आयातों में काफी कमी आई है। आयातों में यह कमी 75% की है। जर्मनी के मामले में आयातों में मामूली वृद्धि हुई है जो 8.9% की है। ब्राजील के मामले में जांच अवधि में कोई आयात नहीं हुए हैं। बुल्गारिया भारत को संबद्ध वस्तु का नियमित आपूर्तिकर्ता नहीं है और आयात पिछले दो वर्षों अर्थात् 1999-2000 और 2000-2001 में ही हुए हैं और आयातों का स्तर कमोबेश समान ही रहा है। उपरोक्त तथ्य संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि होने का कोई खतरा नहीं दर्शाते हैं।

(ख) सामान्य मूल्य

यू के मामले में सामान्य मूल्य घरेलू बाजार में एकल बिक्री दस्तावेज के आधार पर निकाला गया है। सामान्य मूल्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे का निर्धारण केवल एक सौदे के आधार पर नहीं किया जा सकता है। एकल सौदा थोड़ी मात्रा में होने के कारण सौदा हो सकता है अथवा क्रेता के पक्ष में व्यापार शर्तों से सौदा प्रभावित हो सकता है अथवा वह तात्कालिक और बिना बारी की आपूर्ति इत्यदि हो सकती थी। अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए मात्र एकल सौदे का आकलन करना पूर्ण तया भ्रामक होगा।

जर्मनी के मामले में कीमत का निर्धारण किसी तीसरे देश को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने वाले जर्मनी के एक उत्पादक के एकल सौदे की कीमत के आधार पर किया गया है। यहां पुनः

व्यापार के स्तर, शामिल मात्रा और बिक्री की शर्तों पर गौर करना आवश्यक है। इस तथ्य का भी पता लगाना आवश्यक है कि कीमत पर विचार करने के लिए क्या तीसरा देश उपयुक्त देश है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि एकल सौदा छद्म सौदा भी हो सकता है।

ब्राजील और बुल्गारिया के मामले में अपनाई गई लागत संबंधी प्रणाली से उत्पादन लागत के निर्धारण और उसे न्यायोचित ठहराने में लगाए गए अनुमानों का प्रश्न उठता है। चूंकि अनुमान नहीं दिए गए हैं इसलिए इस पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

(ग) क्षति के बारे में साक्ष्य

- याचिका में दिए गए देश वार आयात के आंकड़े सही प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि ये आंकड़े अप्रैल, 2000 से फरवरी 2001 के लिए डी जी सी आई एस के आंकड़ों से भिन्न प्रतीत होते हैं। सही आंकड़े उपरोक्त पैरा 6(iii)(क) में दिए जाने चाहिए।
- जहां तक उत्पादन और क्षमता उपयोग का संबंध है, यहां पर पुनः याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़ों को केवल तीन याचिकाकर्ताओं का उल्लेख कर और समर्थन, उत्पादकों को छोड़कर विकृत कर दिया गया है। यदि समग्र उद्योग के कुल उत्पादन को लिया जाए तो तस्वीर निम्नानुसार बनती है:

वर्ष	एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन (मात्रा टनों में)
1998-99	78,917
1999-2000	79,313
1999-2001	94,704

- इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जांच वर्ष में एक्रिलिक फाइबर के घरेलू उत्पादन में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 20% तक की वृद्धि हुई है।
- जहां तक बाजार हिस्से का संबंध है, सही स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	बाजार हिस्सा			
	उत्पादन टनों में	4 देशों से आयात टनों में	कुल	कुल आयातों का %
1999-2000	79,313	1075	80,388	1.34
2000-2001	94,704	1224	95,928	1.27

- उपरोक्त से यह देखा जाएगा कि घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि आयातों के हिस्से में गिरावट आई है।
- एक्रिलिक नाइट्रिल जो मुख्य कच्ची सामग्री है, की कीमत की तुलना में एक्रिलिक फाइबर की कीमत निम्नलिखित बनती है:-

वर्ष	कीमत प्रति किग्रा	
	एक्रिलिक	एक्रिलो नाइट्रिल
1999-2000	74	31
2000-2001	90	42

- यद्यपि कच्ची सामग्री की लागत में 11 रु० किग्रा तक की वृद्धि हुई है तथापि बिक्री कीमत में 10 रु० प्रति किग्रा तक की वृद्धि हुई है।
- लाभप्रदता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि प्रबंधकीय कुशलता, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी स्तर, मशीनों का युक्तिसंगत स्तर पर रख-रखाव, औद्योगिक संबंध इत्यादि। इसलिए घरेलू उद्योग को हुई हानि, यदि कोई हो, को अधिक आयातों के कारण हुई हानि नहीं कहा जा

सकता है। याचिकाकर्ताओं ने कानूनी रूप से यथोपेक्षित कई मानदंडों के बारे में भी सूचना नहीं दी है।

(घ) कारणात्मक संबंध

कारणात्मक संबंध के बारे में सूचना सही और सटीक नहीं है और घरेलू उत्पादक कारणात्मक संबंध स्थापित करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार याचिकाकर्ता किसी पाटन अथवा क्षति अथवा कारणात्मक संबंध की पुष्टि करने में असफल रहे हैं। अतः आगे की जांच करना न्यायोचित नहीं है और जांच परिणाम में यह कहा जा सकता है कि कोई पाटन नहीं हुआ है और पाटनरोधी शुल्क लगाने का जरूर आधार नहीं है।

(घ) प्राधिकारी द्वारा जांच और जांच परिणाम

7. याचिकाकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अनुरोध की जांच कर उन पर जांच परिणाम निकालते समय विचार किया गया और जहां उचित पाया गया वहां इन पर कार्रवाई की गई है।

8. प्राधिकारी निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संबद्ध देशों के निर्यातकों से पूर्ण एवं पर्याप्त उत्तर न मिलने की स्थिति में, उपरोक्त नियम 6(8) के अनुसार उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध देशों के निर्यातों के बारे में दिए गए जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

9. उपरोक्त नियमावली के अनुसार अनुरोध करने पर प्राधिकारी द्वारा नए निर्यातकों अथवा उन निर्यातकों के मामलों पर विचार किया जाएगा जो कीमतों संबंधी वचन पत्र प्रस्तुत करने के इच्छुक बताए गए हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

10. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद एक्रिलिक फाइबर हैं। एक्रिलिक फाइबर सिंथेटिक पालीमर की एक लंबी श्रृंखला है। जिसमें एक्रिलिक नाइट्रिल यूनिट भार में कम से कम 90% होती हैं।

एक्रिलिक फाइबर एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टो अथवा एक्रिलिक टाप हो सकता है। एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन विभिन्न ग्रेडों में किया जाता है जिन्हें डेनियर के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक्रिलिक फाइबर का अनुप्रयोग परिधान, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। एक्रिलिक फाइबर का वर्गीकरण अध्याय शीर्ष 55.01 और 55.03 में किया जाता है। यह उत्पाद छः अंकीय स्तर पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत 5501.30 और 5503.30 तथा आई टी सी के तहत 5501.3000 और 5503.3000 में वर्गीकृत है। वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद के बारे में है। भले ही उसका वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत उसका आयात किया जाता है कुछ भी हो सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है। ऐसे किसी भी पक्ष ने, जिसने जांच का उत्तर दिया है, इस बात का खंडन नहीं किया है कि संबद्ध देशों द्वारा निर्यातित एक्रिलिक फाइबर और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एक्रिलिक फाइबर समान वस्तुएं हैं। अतः प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया जा रहा एक्रिलिक फाइबर विचाराधीन उत्पाद के समान है।

न्यूनतम सीमाएं

12. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात न्यूनतम से उच्च स्तर पर हुए हैं, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के प्रकाशित आंकड़ों का उल्लेख किया है। डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के मुताबिक जांच अवधि के दौरान वर्गीकरण 55013000 सिंथेटिक फिलोमेंट टो, एक्रिलिक/मोड एक्रिलिक और 55033000 स्टेपल एक्रिलिक फाइबर आफ एक्रिलिक/मोड एक्रिलिक के तहत एक्रिलिक फाइबर का आयात निम्नानुसार रहा है:-

देश का नाम	मात्रा (मी० टन)	आयातों में % हिस्सा
ब्राजील	665.51	4.765
बुल्गारिया	540.29	3.868
जर्मनी	1782.94	12.765
यू.के.	1206.36	8.637

इस प्रकार प्राधिकारी पाते हैं कि जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से हुए आयात न्यूनतम स्तर से अधिक हैं। प्राधिकारी इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन के इस दावे को सही नहीं मानते हैं कि जांच अवधि के दौरान ब्राजील से एक्रिलिक फाइबर के कोई आयात नहीं हुए हैं। दिनांक 28 अगस्त, 2001 की जांच शुरुआत अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एक्रिलिक फाइबर एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टो अथवा एक्रिलिक टोप हो सकता है।

घरेलू उद्योग

13. यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से फोरम ऑफ एक्रिलिक फाइबर मैन्युफैक्चरर्स, नई दिल्ली द्वारा दायर की गई है। भारत में एक्रिलिक फाइबर के निम्नलिखित उत्पादकों ने वर्तमान पाटनरोधी जांच में शामिल होने की विशेष रूप से सहमति दी है:-

- (क) इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड
- (ख) कन्सोलिडेटेड फाइबर एंड कैमिकल्स लिमि०
- (ग) पशुपति एक्रिलोन लिमि०

ऊपर उल्लिखित कंपनियों ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सारी सूचना उपलब्ध कराई है और अपने आपको आगे और सूचना देने और सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया है। इन कंपनियों का कुल भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख अनुपात बनता है। उत्तर देने वाली किसी भी हितबद्ध पार्टी ने याचिकाकर्ता की स्थिति के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है। इस प्रकार प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए उपरोक्त

नियमों के नियम 5(3) (क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के मानदण्ड को पूरा करते हैं। प्राधिकारी इन याचिकाकर्ता कम्पनियों को उक्त नियम 2(ख) के अर्थों में 'घरेलू उद्योग' मानते हैं।

ड. पाटन और सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के बारे में किए गए दावों की जांच

सामान्य मूल्य

14. सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

(i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो, या

(ii) जहां निर्यातक देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की समुचित तुलना नहीं हो सकती हो, तो सामान्य मूल्य या तो:-

(क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किये जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य ; या

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत जिसमें प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि की गई हो।

15. प्राधिकारी ने धारा 9 क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारण के प्रयोजन से सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी । प्राधिकारी को निम्नलिखित निर्यातकों और निर्यातक संघों से उत्तर प्राप्त हुए ।

- i. एकोर्डिस यू के लि0, यू के
- ii. मै0 लुकोइल ऑयल कंपनी, बुल्गारिया
- iii. ड्यूपोंट ड्यूस्च लैंड होल्लिंग जीएमबीएचएंड कंपनी के जी, जर्मनी
- iv. ड्रेलोन जीएमबीएच - बेयरवर्क, जर्मनी
- v. इंटरनेशनल रेयॉन एंड सिंथेटिक फाइबर्स कमेटी (सीआईआरएफएस), ब्रुसेल्स ।

तथापि, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को मोटे तौर पर प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त और अपूर्ण पाया गया, जैसा कि नीचे विस्तारपूर्वक विचार किया गया है ।

यू के के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यू के के किसी भी निर्यातक ने पूर्ण उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है ।

केवल मै0 एकोर्डिस, यू के ने उत्तर दिया है और कीमत के बारे में वचनबद्धता देने का प्रस्ताव किया है । उन्होंने प्रश्नावली के परिशिष्ट 1 से 10 और भाग क से ज के तहत अपेक्षित पूरी सूचना नहीं दी है । नियम 15(2) के अनुसार " उप-नियम (1) के खण्ड (ii) के अंतर्गत कीमत वृद्धि के सम्बन्ध में किसी भी निर्यातक से कोई वचनबद्धता स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटन और क्षति का प्रारंभिक निर्धारण न कर लें । " इसलिए पाटन और क्षति का प्रारंभिक निर्धारण करना प्राधिकारी पर निर्भर करता है । चूंकि यू के में सम्बद्ध वस्तु के घरेलू बिक्री कीमत ढांचे, प्रश्नावली के अनुसार इसकी उत्पादन की लागत और अन्य सूचना के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा करके कार्रवाई की है । याचिकाकर्ताओं ने यू के के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा एक अकेले बिक्री बीजक पर आधारित यू के में घरेलू बिक्री के साक्ष्य के आधार पर किया है । भारतीय स्पिनर्स संघ ने यह उल्लेख किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण एक अकेले सौदे के आधार पर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वास्तव में प्रतिनिधिक सौदा नहीं हो सकता ।

17. इंटरनेशनल रेयॉन एंड सिंथेटिक फाइबर्स कमेटी (सीआईआरएफएस), बुसेल्स के अनुसार याचिका में शामिल यू के के सामान्य मूल्य का मूल्यांकन बहुत भ्रामक है। जैसा कि याचिका में दावा किया गया है, यू के के मामले में 2.67 डालर का सामान्य मूल्य विशिष्ट उत्पादों के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी पाते हैं कि किसी भी निर्यातक ने सम्पूर्ण और पर्याप्त सूचना नहीं दी है ताकि वे घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकें। पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1(2) के अनुसार निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समान वस्तु की बिक्री व्यापार के सामान्य दौर में होनी चाहिए। प्राधिकारी सीआईआरएफएस के विचार को स्वीकार नहीं कर सकता, जब तक कि ऐसे दावे प्रश्नावली में यथा-अपेक्षित पूरी सूचना द्वारा समर्थित न हों। प्राधिकारी सम्बद्ध देशों के निर्यातकों से निर्धारित प्रपत्र तथा तरीके में पूर्णतया तथा पर्याप्त उत्तर प्राप्त होने के अभाव में उपरोक्त नियम 6(8) के अनुसार अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सम्बद्ध देशों से हुए निर्यातों के संबंध में जांच-परिणाम देने की पुष्टि करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए याचिकाकर्ता द्वारा यथा-प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करते हैं, अर्थात् याचिकाकर्ता द्वारा यथा-प्रस्तुत घरेलू बिक्री सौदे के अनुसार। इस प्रकार यू के के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य *** यूएस डालर है।

जर्मनी के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण

18. जर्मनी के निर्यातकों में से केवल मै0 ड्यूपोंट और मै0 ड्रेलोन ने उत्तर दिया है। मै0 ड्यूपोंट ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत को एक्रिलिक फाइबर का निर्यात नहीं किया है क्योंकि उन्होंने 1990 के दशक के आरंभ में एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन बंद कर दिया था। मै0 ड्रेलोन, जो कि मै0 बेयर फासर जी एम बी एच का कानूनी उत्तराधिकारी है, ने जांच अवधि के दौरान भारत को 994 मै0 टन का निर्यात किया है। उन्होंने पूर्ववर्ती वर्षों के निर्यात के बारे में सूचना दी है और बताया है कि भारत के साथ उनका व्यवसाय जांच अवधि के दौरान 26 % तक कम हुआ है। तथापि उन्होंने प्रश्नावली के परिशिष्ट 1 से 10 और भाग क से ज के तहत अपेक्षित पूर्ण सूचना नहीं दी है। भारतीय स्पिनर्स संघ के अनुसार एक तीसरे देश को जर्मनी से निर्यात के अकेले सौदे से व्यापार के स्तर, शामिल मात्रा और बिक्री की शर्तों के बारे में जानना पर्याप्त नहीं होगा। सीआईआरएफएस के अनुसार, याचिका में जर्मनी में 1.66 डालर का सामान्य मूल्य उन विशेष

उत्पादों के आधार पर किया गया है, जो कि सामान्यतः भारत को निर्यातित उत्पादों से तुलनीय नहीं हैं। प्राधिकारी दोहराते हैं कि पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1(2) के अनुसार निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समान उत्पाद की बिक्री व्यापार के सामान्य दौर में होनी चाहिए। प्राधिकारी सी आईआरएफएस और भारतीय स्पिनर्स संघ के विचार को स्वीकार नहीं कर सकता, जब तक कि ऐसे दावे प्रश्नावली में यथा-अपेक्षित पूरी सूचना द्वारा समर्थित न हों। प्राधिकारी सम्बद्ध देशों के निर्यातकों से निर्धारित प्रपत्र तथा तरीकें में पूर्ण तथा पर्याप्त उत्तर प्राप्त होने के अभाव में उपरोक्त नियम 6(8) के अनुसार अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सम्बद्ध देशों से हुए निर्यातों के संबंध में जांच-परिणाम देने की पुष्टि करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए याचिकाकर्ता द्वारा यथा-प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया है, अर्थात् याचिकाकर्ता द्वारा यथा प्रस्तुत तीसरे देश को जर्मनी से हुए निर्यातों के साक्ष्य के अनुसार। इस प्रकार जर्मनी के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य *** यू एस डालर है।

बुल्गारिया के संबंध में सामान्य मूल्य निर्धारण

19. मै0 ल्यूकोइल कंपनी ने भारत को किए गए निर्यातों की कुल मात्रा और उनका मूल्य, अन्य देशों को निर्यात और घरेलू बिक्री के बारे में सूचना दी है। औसत इकाई कीमत भी दी गई है। तथापि, प्रश्नावली के परिशिष्ट 1 से 10 और भाग क से ज में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। प्राधिकारी पाते हैं कि सूचना मोटे तौर पर अपर्याप्त और अपूर्ण है। पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1(2) के अनुसार बुल्गारिया के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना अपर्याप्त और अपूर्ण होने के कारण प्राधिकारी इस सूचना को स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समान उत्पाद की बिक्री व्यापार के सामान्य कोर्स में होनी चाहिए। प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि सम्बद्ध देश के निर्यातकों से निर्धारित रूप तथा प्रपत्र में पूर्ण तथा पर्याप्त उत्तर प्राप्त न होने पर उन्हें उपरोक्त नियम 6(8) के अनुसार अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सम्बद्ध देश से हुए निर्यातों के संबंध में जांच परिणाम देने पड़े हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए याचिकाकर्ता द्वारा यथा प्रस्तुत उपलब्ध सूचना पर विचार किया है अर्थात् सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन की परिकलित लागत के अनुसार। बुल्गारिया के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य *** डालर है।

ब्राजील के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण:

20. ब्राजील के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। घरेलू उद्योग ने ब्राजील के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर किया है। उन्होंने प्रमुख कच्ची सामग्री एक्रिलोनाइट्राइल की कीमत का निर्धारण मुख्य दैनिक में इस मद की प्रकाशित कीमत के आधार पर किया है। तदनुसार, ब्राजील के संबंध में परिकलित सामान्य मूल्य *** यूएस डालर बनता है।

यू के और जर्मनी के संबंध में निर्यात कीमत:

21. यू के और जर्मनी के किसी भी निर्यातक ने निर्यात कीमत प्रस्तुत करने में सहयोग नहीं दिया है। याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। अप्रैल 2000-मार्च 2001 की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हैं। एक्रिलिक फाइबर के आयातों के आंकड़े, वर्गीकरण 55013000¹ ***

‘ सिंथेटिक फिलामेंट टो, एक्रिलिक/मोड-एक्रिलिक’ तथा 55033000 ‘स्टेपल फाइबर्स ऑफ एक्रिलिक/मोड-एक्रिलिक’ के तहत दर्शाए गए हैं। प्राधिकारी ने यू के और जर्मनी के संबंध में इन आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया है। याचिकाकर्ता ने समुद्री भाड़े, बीमे, कमीशन, अंतर्राज्यीय परिवहन और पत्तन हैंडलिंग प्रभारों के लिए समायोजन दर्शाए हैं। प्राधिकारी ने 50 डालर/मी0 टन की दर पर समुद्री भाड़े के कारण *** डालर, बीमा सी आईएफ का .5 %, कमीशन सीआईएफ का 2%, समुद्री भाड़ा एफ ओ बी का 2% और पत्तन प्रभार सी आई एफ का 2 % पर समायोजनों की अनुमति दी है। यू के के लिए कारखानागत निर्यात कीमत *** यू एस डालर बनती है। ऐसे ही समायोजनों की अनुमति देने के पश्चात जर्मनी के संबंध में कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत *** यू एस डालर बनती है।

बुलगारिया के संबंध में निर्यात कीमत

22. मैसर्स ल्यूकॉयल कम्पनी ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है लेकिन उन्होंने अपर्याप्त एवं अधूरी सूचना दी है। उन्होंने परिशिष्ट 2 में दिए गए प्रपत्र में भारत को किए गए निर्यातों के सौदे-वार ब्यौरे नहीं दिए हैं। इसकी बजाय इन्होंने कुल निर्यात बिक्रियों, अन्य देशों को हुए कुल निर्यातों और संबंधित यूनिट कीमत के साथ कुल घरलू बिक्रियों के ब्यौरे दिए हैं। प्राधिकारी ने उक्त सूचना को अपर्याप्त एवं अधूरा पाया है। तथापि, यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान निर्यातक ने 868 एमटी के निर्यातों को दिखाया है। उत्तर में दिखाई गई कीमत का एफसीए बओरगैस सुपुदगी और अग्रिम भुगतान के रूप में उल्लेख किया गया है। भारत के लिए सीआईएफ निर्यात कीमत के बारे में स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना और प्रश्नावली के अनुसार अन्य सूचना के अभाव में प्राधिकारी निर्यातक द्वारा यथा-प्रस्तुत निर्यात मात्रा और निर्यात कीमत के बारे में सीमित सूचना को भी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजन से डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया जा ... डालर सीआईएफ बैठती है। 50 डालर/एमटी की दर से समुद्री भाड़ा, सीआईएफ का 0.5% बीमा, सीआईएफ का 2% कमीशन, एफओबी का स्वदेशी भाड़ा और सीआईएफ का 2% पत्तन प्रभार के कारण ... डालर का समायोजन करने के पश्चात कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत ... डालर बनती है।

ब्राजील के लिए निर्यात कीमत

23. ब्राजील के किसी निर्यातक से कोई जवाब नहीं मिला है। अतः प्राधिकारी ने निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है। इस सूचना के अनुसार भारत और सीआईएफ निर्यात कीमत ... अमरीकी डालर बैठती है। 50 डालर/एमटी की दर से समुद्री भाड़ा, सीआईएफ का 0.5% बीमा, सीआईएफ का 2% कमीशन, एफओबी का 2% स्वदेशी भाड़ा और सीआईएफ का 2% पत्तन प्रभारों के संबंध में समायोजन किए गए हैं। कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत ... अमरीकी डालर बनती है।

पाटन मार्जिन

24. उपरोक्तानुसार निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करत हुए पाटन मार्जिन निम्नानुसार बनता है:-

क्र.सं.	देश	पाटन मार्जिन %
1	यू.के.	80.80 %
2.	जर्मनी	10.51 %
3.	बुल्गारिया	51.11 %
4	ब्राजील	229.72 %

(ड.) क्षति

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में निम्नानुसार उल्लेख है-

क्षति का निर्धारण

- विनिर्दिष्ट दशों से हुए आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करेगा कि भारत में ऐसी वस्तु के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग का वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा उत्पन्न होता है अथवा किसी उद्योग को स्थापित करने में अत्यधिक बाधा आती है।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी घरलू उद्योग को हुई क्षति, घरलू उद्योग का होने वाली क्षति के खतरा, घरलू उद्योग की स्थापना में आने वाली अत्यधिक बाधा और पाटित आयातों एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण पाटित आयातों की मात्रा समान वस्तुओं के लिए घरलू बाजार में कीमतों पर इसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरलू उत्पादकों पर इस आयातों का परिणामी प्रभाव समेत संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इन नियमों के अनुबंध-11 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार करेगा।

26. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-11 में उल्लिखित क्षति के निर्धारण संबंधी सिद्धांतों में यह उपबंध किया गया है कि:

(क) क्षति के निर्धारण में इन दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी:- (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु की घरेलू बाजार कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव ।

(ख) पाटित आयातों की मात्रा की जांच करत समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अथवा समग्र रूप में पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । नियम-18 के उप-नियम (2) में यथा-उल्लिखित कीमता पर पाटित आयातों के प्रभावों के संदर्भ में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या पाटित आयातों से भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमतों में काफी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों से अन्यथा काफी हद तक कीमतों में कमी आयी है अथवा कीमता में वृद्धि हानि से रोक रखा गया है या अन्यथा काफी हद तक बढ़ गयी होती ।

27. प्राधिकारकर्ताओं के विचार

- i) घरेलू उद्योगों को विभिन्न देशों से एकीलिक फाइबर के पाटन से क्षति हो रही थी और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूएसए, थाईलैंड, कोरिया जनवादी गणराज्य, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, जापान, मेक्सिका, तुर्की और ताइवान से हुए एकीलिक फाइबर के आयातों के संबंध में जांच की है । स्पष्टतः घरेलू उद्योगों को एक के बाद एक विभिन्न स्त्रोतों से पाटन के कारण नियमित रूप से क्षति हुई है ।
- ii) यूक्रेन, जर्मनी, बाजील और बुल्गारिया के निर्यातक भारत में एकीलिक फाइबर का पाटन कर रहे हैं और निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के तहत यथा-अपेक्षित भिन्न-भिन्न स्त्रोतों से इन पाटित आयातों के संचयी प्रभाव की जांच कर सकता है ।
- iii) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है ।
- iv) संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है ।
- v) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योगों के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में कमी आई है ।

- vi) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है तथापि, उद्योग विभिन्न स्त्रातों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी उचित कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा है क्योंकि नए स्त्रातों से आयात शुरू कर दिए गए हैं
- vii) वर्ष 2000-2001 के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में 17% से भी ज्यादा तक की गिरावट आई है जिसका सीधा कारण कुछक ग्राहकों का पाटित आयातों की ओर आकर्षित होना था
- viii) यद्यपि, याचिकाकर्ता कंपनियों में राजगार के स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है तथापि, यदि मौजूदा स्थिति जारी रहती है तो घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन रोकना/बंद करना होगा जिसका राजगार पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा
- ix) उत्पादन लागत और उचित बिक्री कीमत में पर्याप्त, कम कीमती पर एक्रिलिक फाईबर की बिक्री के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का भारी हानि हुई है। एक के बाद एक स्त्रात से पाटन जारी रहने से घरेलू उद्योग अपने उत्पादों को इस कीमत पर बेचने के लिए बाध्य हुआ है जिस पर पूरी उत्पादन लागत भी प्राप्त नहीं की जा सकती है
- x) घरेलू उद्योग का हा रही क्षति का प्रत्यक्ष कारण संबद्ध देशों से हुए पाटित आयात हैं।

28. निर्यातकों और आयातकों के विचार

i) इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन के अनुसार

- यू.के. से एक्रिलिक फाईबर के आयातों में 1997-98 के बाद पर्याप्त कमी आई है। आयातों में यह कमी 75% तक की है। जर्मनी के मामले में आयातों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है जो 8 से 9% तक की है। ब्राजील के मामले में, जांच अवधि में कोई आयात नहीं हुआ है। बुल्गारिया भारत को संबद्ध वस्तु का नियमित आपूर्तिकर्ता नहीं है और केवल पिछले दो वर्षों अर्थात् 1999-2000 और 2000-2001 में ही आयात किए गए हैं, और आयातों का स्तर क्रमोद्देश समान रहा है। उपरोक्त तथ्यों से संबद्ध देशों से हुए आयातों में वृद्धि का कोई खतरा प्रदर्शित नहीं होता है।

- जांच के वर्ष में एक्रिलिक फाइबर के घरेलू उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 20% तक की वृद्धि हुई है
- घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि आयातकों के हिस्से में गिरावट आई है ।
- हालांकि कच्ची सामग्री की लागत में 11 रूपए/किग्रा तक की वृद्धि हुई है तथापि बिक्री कीमत 16 रूपए/किग्रा तक बढ़ गई है ।
- लाभप्रदता विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है जस प्रबंधन कुशलता, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी का स्तर, मशीनों का युक्तिसंगत स्तर पर रख-रखाव, औद्योगिक सबध इत्यादि । इस प्रकार, घरेलू उत्पादकों को हुई हानि यदि कोई हो, में आयतों के कारण वृद्धि हो सकती है ऐसा कहा नहीं जा सकता है ।

ii) मैसर्स ड्रैलॉन जीएमबीएच, जर्मनी के अनुसार, भारत में लगभग 1,20,000 टन/वार्षिक मिल खपत की तुलना में जांच अवधि के दौरान उनका बाजार हिस्सा लगभग 0.8% था और इस बाजार हिस्से के साथ वे भारतीय घरेलू उत्पादकों के लिए कोई खतरा नहीं देखते हैं (न्यूनतम सीमा संबंधी नियमों के अनुसार) । उनके अनुसार, जांच अवधि के दौरान भारतीय घरेलू एक्रिलिक फाइबर के उत्पादकों की लगभग 93-94% की क्षमता-उपयोग दर इस स्तर पर कार्य निष्पादन का दर्शाती है जो विश्व-व्यापी उद्योग के औसत के बराबर या इससे अधिक है ।

iii) सीआईआरएफएस के अनुसार

यू.क. और जर्मनी से भारत का हुए आयातों का बाजार हिस्सा काफी कम स्तर पर रहा है । जर्मनी के मामले में 2000-2001 में बाजार हिस्सा केवल 1.7% और यू.क. के मामले में 1.1% माना जा सकता है । ये बाजार हिस्से भारतीय उत्पादकों की क्षति पहुँचाने के लिए काफी कम हैं और उनके अनुसार ये घरेलू उद्योगों का हुई क्षति के असल कारण निम्नानुसार हैं :

(क) अपर्याप्त आकार

याचिकाकर्ताओं के सयंत्रों की औसत आकार 12,000 टन से 38,500 टन के बीच है जिसका औसत 24,000 टन बनता है । यह उस लाभकारी आकार से काफी कम है जो एक्रिलिक फाइबर के उत्पादन एकका का प्रभावी ढंग से चलाने के लिए जरूरी है । यू.क. और जर्मनी में सयंत्रों का आकार 70,000 टन से लेकर 1,50,000 टन तक रहता है । विश्व में अन्यत्र कुछ सयंत्रों का आकार 20,000

टन से ज्यादा हैं। याचिकाकर्ता के लिए आयातों की असबद्ध गंभीर समस्याएँ तब तक बनी रहेगी जब तक वे अलाभकारी उत्पादन आकार वाले एककों का चलाना जारी रखेंगे।

(ख) अपर्याप्त तकनीक

कुछ मामलों में भारत के संयंत्र पुराने हो गए हैं। कुछ पुराने संयंत्रों का काफी साल पहले आयात किया गया था और कुछ प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अप्रचालित हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन लागत अधिक है, गुणवत्ता अविश्वसनीय है और यह कि उत्पादक समस्त प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति करने में असमर्थ हैं।

(ग) भारतीय वस्त्र उत्पादन का हुई क्षति का कारण एकीलिक फाइबर के उत्पादकों का प्रदान किया गया अत्यधिक संरक्षण है।

प्राधिकारी द्वारा जॉच

29. प्राधिकारी ने जांच अवधि और पिछले वर्षों के दौरान संबद्ध देशों से हुए निर्यातों की मात्रा के संबंध में सूचना की जांच की है। जांच अवधि के दौरान चारों संबद्ध देशों से आयात 4195 एमटी के हुए थे। वर्ष 1999-2000 के दौरान ये आयात 2469 एमटी के हुए थे और 1998-99 के दौरान 3739 एमटी के हुए थे (डीजीसीआई एंड एस के आकड़ों के अनुसार)। इन आयातों का बाजार-हिस्सा 1998-99 में 3.35%, 1999-2000 में 2.18% और 2000-2001 के दौरान 3.73% बनता है। पिछले वर्ष 1999-2000 में तुलना करने पर जांच अवधि के दौरान बाजार हिस्से में उल्लेखनीय बढ़ाव प्रदर्शित हुआ था। तथापि, मात्रा के रूप में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयातों में पिछले वर्षों में हुए आयातों की तुलना में 69% की वृद्धि दिखाई देती है। यद्यपि बाजार हिस्से में हुई वृद्धि पर्याप्त नहीं है तथापि यह उल्लेखनीय रही है और आयातों में समग्र रूप से हुई वृद्धि से घरेलू उद्योग का कोई खतरा नहीं है। प्राधिकारी ने पाया है कि पाटित आयातों में समग्र रूप में वृद्धि हुई है।

30. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक कम करना है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुँच

कीमत की तुलना निवल बिक्री प्राप्ति से की है और यह पाया है कि पाटित आयातों से कीमतों में पर्याप्त कटौती हुई है। आयातों की पहुँच कीमत को घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम पाया गया है। आयातों से घरेलू बाजार की कीमतों में पर्याप्त कमी/ह्रास हो रहा था क्योंकि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण अपनी बिक्री कीमत को बढ़ाने में असमर्थ रहा है।

31. भारत में घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच के लिए प्राधिकारी ने क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री, निवल बिक्री प्राप्ति, लाभप्रदता इत्यादि जैसे संकेतकों पर भी विचार किया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। प्राधिकारी ने पाया है कि :-

(क) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उन कीमतों से काफी कम है जिनसे घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन लागत को उचित प्राप्ति हुई होगी और उससे समुचित आय प्राप्त की जाएगी।

(ख) जांच अवधि के दौरान तीनों याचिकाकर्ता कंपनियों की संस्थापित क्षमता में वृद्धि हुई थी। तथापि पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता कंपनियों के कुल उत्पादन में गिरावट आई है। पहले पैरा 2 (ii) में उल्लिखित दो अन्य घरेलू उत्पादकों जिन्होंने याचिका का समर्थन तो किया है किन्तु वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के उत्पादन में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हो सकती है। इण्डियन स्पिनर्स एसोसिएशन का तर्क यह है कि जांच अवधि के दौरान एक्रिलिक फाइबर के उत्पादन में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता कंपनी का 61% हिस्सा अर्थात् जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक बड़ा प्रतिशत बनता है और उक्त उपर्युक्त नियम 2(ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग" माना गया है और ऐसा ही उल्लेख इन जांच परिणामों के पूर्वोक्त पैरा-13 में किया गया है। अतः प्राधिकारी का विचार है कि घरेलू उद्योग का क्षति उत्पादन और क्षमता उपयोग में आई गिरावट के कारण हुई है। याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा यथा प्रदर्शित घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में भी पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 16.25% की गिरावट आई है।

(ग) हालाँकि पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जाँच अवधि में बिक्री कीमतों में वृद्धि हुई थी, लेकिन उत्पादन लागत में वृद्धि बिक्री कीमतों में हुई वृद्धि से काफी अधिक थी। वस्तुतः यह पाया गया है कि जाँच अवधि के दौरान प्रति इकाई घाटे में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार पाटित आयातों में उचित कीमत प्राप्त करने में घरेलू उद्योग का समुचित कीमत वृद्धि करने में सफलता नहीं मिली है। उद्योग को कम बिक्री कीमतों के कारण वास्तविक क्षति हुई है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत की वसूली नहीं हो सकी और इसलिए वित्तीय घाटा उठाना पड़ा।

क्षति का संचयी मूल्यांकन

32 अनुबन्ध-II (iii) के अनुसार यदि एक से अधिक देशों से होने वाले उत्पादों के आयातों की पाटनराशी जांच होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निर्धारित करने के बाद ही ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेगा कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में प्रमाणित डुपिंग का मार्जिन 2% से अधिक है जो निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है तथा प्रत्येक देश से होने वाले आयातों की मात्रा समान वस्तुओं के आयातों का 3 % है और (ख) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित सामान तथा वैसे ही घरेलू सामानों के बीच प्रतियोगिता की शर्तों का ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है। प्राधिकारी ने पाया है कि प्रत्येक संबद्ध देश के मामले में पाटन मार्जिन 2% से अधिक है और प्रत्येक देश के आयातों की मात्रा भी 3 % से अधिक है। प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि घरेलू तौर पर उत्पादित समान वस्तु पर संबद्ध वस्तु के आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करना उचित होगा और यह पाया है कि घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण क्षति का संचयी प्रभाव पड़ा है।

(छ) कारणात्मक संबंध

33. जहाँ तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है पाटनराशी नियमों के अनुबन्ध-1 के नियम (iv) में यह व्यवस्था है कि :

“संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संबद्ध आर्थिक कारकों और संकेतकों की जांच शामिल होगी जोकि घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जैसे बिक्री में

वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, निविष्टि, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश से आय अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमतों का प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा नकद प्रवाह स्टॉक पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, राजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूँजी निवेश में वृद्धि की क्षमता आदि ।

याचिकाकर्ताओं के विचार:

34 याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उद्योग की क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है । चूंकि संबद्ध वस्तुओं का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है इसलिए उद्योग का अपनी बिक्री कीमत को उत्पादन लागत से काफी कम रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है । इसलिए उद्योग क्षतिरहित कीमत वसूल करने में सक्षम नहीं है । पाटित आयातों के कारण हुई कीमत कटौती के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का गंभीर वित्तीय घाटा हुआ है । उद्योग का अपनी बिक्री और उत्पादन में वृद्धि करने में भी रूकावट आई है । घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में कोई कमी नहीं हुई है और उद्योग का हुई क्षति के लिए मांग में किसी गिरावट का जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता है ।

प्राधिकारी द्वारा जाँच और जाँच परिणाम

35. प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध के बारे में भारतीय बुनकर संघ और सीआईआरएफएस के दृष्टिकोणों पर भी विचार किया है जिसका पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है । प्राधिकारी अपने विचारों में उक्त हितबद्ध पार्टियों द्वारा बतलाए गए कारणों में ऐसा कोई कारण नहीं देखते हैं जिससे कि मौजूदा जाँच में घरेलू उद्योग को हानि वाली क्षति के लिए उत्तरदायी माना जा सके । भारत में घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जाँच के लिए प्राधिकारी ने उक्त नियम के अनुबंध-II (iv) के अनुसार ऐसे कारकों पर विचार किया है जोकि घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जैसकि उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली आदि । प्राधिकारी ने यह भी पाया है कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग पूर्ववर्ती वर्ष 1999-2000 की मांग के लगभग समान रही है ।

36 उपरोक्तानुसार विभिन्न आर्थिक मानकों की जाँच के बाद प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचे हैं -

- (i) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण उच्चतर क्षमता के उपयोग में बाधित होना पड़ा है।
- ii) सम्बद्ध दशों से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- (iii) घरेलू उद्योग की बिक्री में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- iv) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में जांच अवधि के दौरान वर्ष 1999-2000 की तुलना में वृद्धि हुई है। तथापि, यह पाटित आयातों के कारण क्षतिरहित कीमत से कम रही है।
- v) उद्योग का पाटित आयातों की कीमत कटाती के कारण वित्तीय घाटा हुआ है।
- vi) घरेलू उद्योग का कीमत कटौती के कारण घाटा हुआ है। व उत्पादन लागत की वसूली के लिए अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर सका है क्योंकि पाटित आयातों की पहुँच कीमत उत्पादन लागत से काफी कम रही है।
- vii) उपरोक्त मानदंड आर्थिक, सामूहिक तथा सचयी रूप से यह प्रमाणित करते हैं कि घरेलू उद्योग का पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

(ज) भारतीय उद्योग के हित

37 सामान्य तौर पर पाटनराधी शुल्क लगान का उद्देश्य एस पाटन का समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग का नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की पुनः स्थिति लाना है ताकि देश के सामान्य हित में है।

38 प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनराधी शुल्क लगान से सम्बद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों की कीमतें स्तर प्रभावित होंगी और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि पाटनराधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, इसके विपरीत पाटनराधी उपायों का लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होगा, भारतीय उद्योग का ह्रास रूकगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रहेंगे। प्राधिकारी नाट करते हैं कि पाटनराधी उपायों से संबद्ध दशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे, और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए इस उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(झ) निष्कर्ष

उपरोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि

- (i) एक्रीलिक फाइबर का सबद्ध देशों से भारत का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है,
- (ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है,
- (iii) वास्तविक क्षति सबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है.

40. घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के प्रयाजन से प्राधिकारी ने जाँच होने तक संबद्ध देशों से एक्रीलिक फाइबर के सभी आयातों पर अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझा है । प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन उपरोक्त पैराग्राफों में दर्शाया गया है । प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन या क्षति के मार्जिन जो भी इनमें से कम हो, से कम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का प्रस्ताव किया है जिसे अगर लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त हो जाएगी । क्षति के निर्धारण के प्रयाजन से आयातों के पहुँच मूल्य की तुलना जाँच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनियों की क्षति रहित बिक्री कीमत के साथ करने का प्रस्ताव है ।

41 तदनुसार प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि अन्तिम निर्धारण, होने तक सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण की अनुसूची-1 के अध्याय-55 के अंतर्गत आने वाले यू.के., जर्मनी, बुल्गारिया और ब्राजील मूल के या वहाँ से निर्यातित एक्रीलिक फाइबर के सभी आयातों पर कन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाय । पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित सारणी के कालम-3 के अनुसार होगा:

क्रम सं.	देश	पाटनरोधी शुल्क (अमरीकी डालर प्रतिकिग्रा)
1	यू.के. के सभी उत्पादक/निर्यातक	0.684
2	जर्मनी के सभी उत्पादक/निर्यातक	0.143
3.	बुल्गारिया के सभी उत्पादक/निर्यातक	0.619
4.	ब्राजील के सभी उत्पादक/निर्यातक	1.275

42 इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य हागा और उसमें सीमाशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्का का छाड़कर सभी प्रकार के शुल्क शामिल होंगे ।

अ. आगे की प्रक्रिया

43. प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों से इन निष्कर्षों के बारे में टिप्पणियाँ आमंत्रित करेंगे और उन पर अंतिम निष्कर्षों में विचार किया जाएगा;

(ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ताओं तथा अन्य ज्ञात हितबद्ध पार्टियों का अलग से लिखा जा रहा है, जो इस प्रारंभिक जांच परीणाम के जारी होने की तारीख से 40 दिनों के अन्दर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकती है,

(ग) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों का मौखिक अनुरोध करने का अवसर प्रदान करेंगे । जिन्हें उससे बाद लिखित में प्रस्तुत करना होगा ।

(घ) प्राधिकारी आवश्यक समझी गई सीमा तक उस पर आगे जाँच करेंगे

(ड.) अन्तिम निष्कर्षों की घोषणा करने से पहले प्राधिकारी आवश्यक तथ्यों का प्रकट करेंगे

एल.पी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2001

Preliminary Findings

Subject :—Anti-dumping investigation concerning imports of Acrylic Fibre originating in or exported from UK, Germany, Brazil and Bulgaria—Preliminary findings.

No. 42/1/2001-DGAD.— The Government of India having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

A. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed:-

- (i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from Forum of Acrylic Fiber Manufacturers, New Delhi on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as subject goods) originating in and exported from UK, Germany, Brazil and Bulgaria (hereinafter referred to as subject countries) ;
- (ii) The following producers of acrylic fibre in India and members of the Forum (hereinafter referred to as the petitioners) have specifically consented to participate in the anti-dumping investigations:
 - a) M/s Indian Acrylics Limited, having its office at:
SCO, 49-50, Sector 26,
Chandigarh.
 - b) M/s Consolidated Fiber and Chemicals Limited, having its office at:
97, Park Street 3rd, Kolkata.
 - c) M/s Pasupati Acrylon Limited, having its office at:
M-14, Connaught Place, New Delhi.

Two other domestic producers, viz., M/s. Indian Petrochemicals and Chemicals Ltd., Baroda; and M/s. Vardhman Acrylics Ltd., Ludhiana have supported the petition.

- (iii) The Authority notified the Embassies of UK, Germany, Brazil and Bulgaria in India about the receipt of dumping application made by the petitioners before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;
- (iv) The Authority issued a Public Notice dated 28th August, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of Acrylic Fibre falling under Chapter heading/subheading 5501.30 and 5503.30 of Schedule I of the Customs Tariff Act.
- (v) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers, industry associations and to the complainants and gave them an opportunity to make their views known in writing.
- (vi) According to sub-rule (3) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the petition to all the known exporters and Embassies of subject countries in India.
- (vii) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following exporters:

1. Acordis Ag,
Kasinostrasse 19,
42103, Wuppertal,
Germany.

2. Bayer Faser Gmbh,
41538, Dormagen,
Gesellschafften Faserwerke Lingen,
Gvw Garnveredlingswerke Gmbh, Goch,
Germany.

3. Markische Faser Ag,
Parkstrasse,
14727, Premnitz,
Germany.

4. Du Pont De Nemours (Deutschland),
Du Pont Strasse 1,
61352, BAD HOMBURG V.D.H,
Germany.

5. Accordis,
Westcrogt, Saint Street,

Bradford,
U.K.

6. Neftokhim Petrochemical Complex,
Acrylic Fibre Complex,
Burgas,
Bulgaria.

7. Rhodia Bresil Crylor,
Acrylic Fibre Division,
Centro Empresarial A.V. Maria,
Coelho Aguiar 215,
Bloco B, Cep05804-902,
Sao Paulo,
Brazil.

- (viii) The Embassies of subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of investigation and requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;
- (ix) The questionnaire was sent to the following users/importers/association of subject goods:

M/s. Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd.,
Bhilwara Bhawan,
40-41, Community Center,
New Delhi – 110 065.

M/s. Siddharth Super Spinning Mills Ltd.,
211, Gagan Deep,
12, Rajendra Place,
New Delhi – 110 008.

M/s. Adhinath Textiles Ltd.,
Village – Bholapur,
P.O. Sahabana Mundia,
Ludhiana,
Punjab.

M/s. Vardhaman Spinning & General Mills,
Chandigarh Road,
Ludhiana – 141 011,
Punjab.

M/s. Malwa Cotton Spinning Mills Ltd.,
Industrial Area, 'A',
Ludhiana – 141 003,
Punjab.'

M/s. Winsome Textile Industries Ltd.,
SCO 144-145, Sector 34-A,
Chandigarh – 160 022.

M/s. Bhiwani Textile Mills,
Bhiwani (Dist. Hissar),
Haryana.

M/s. Shruti Synthetics Ltd.,
Village Loyaran, Gagunda Road,
Udaipur,
Rajasthan.

M/s. Nahar Spinning Mills Ltd.,
373, Industrial Area – A,
Ludhiana – 141 003,
Punjab.

Indian Spinners' Association,
C/o The Millowners' Association,
Elphinstone Building,
10, Veer Nariman Road,
Fort, Mumbai – 400 001.

- (x) Additional information regarding injury was sought from the petitioners, which was also furnished;
- (xi) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;
- (xii) ***** in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;
- (xiii) The investigation covered the period from 1st April, 2000 to 31st March, 2001;
- (xiv) Copies of initiation notice were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc., for wider circulation.

B. PETITIONER'S VIEWS

- 3. The petitioners have made the following major arguments in their submissions:-
 - i. The product under consideration in the present petition is Acrylic Fibre

- ii. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units. Acrylic fibre can be acrylic staple fibre, acrylic tow or acrylic top. Acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are all known as acrylic fibre. The only difference between acrylic fibre and acrylic tow is the difference in length. Acrylic Fibre is produced in various grades, which are defined in terms of its Denier. Acrylic Fibre is an economical substitute for expensive wool. Acrylic Fibre has application in day to day human life use. Acrylic Fibre has a variety of applications in apparel, house-hold and industrial areas.
- iii. Acrylic Fibre (which includes tow, top and staple) is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act at subheading nos. 5501.30 and 5503.30.
- iv. There is no known difference in Acrylic Fibre produced by the Indian industry and the Acrylic Fibre exported from the subject countries. The Acrylic Fibre produced by the Indian industry and that imported from the subject countries is comparable in terms of characteristics, such as, physical and chemical, manufacturing process and technology, functions and uses, products specification, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Therefore, the Acrylic Fibre produced by the domestic industry should be treated as like article to the subject goods imported from subject countries within the meaning of the Rules supra.
- v. The petitioners represent the domestic industry as they have a majority share in the domestic production of Acrylic Fibre.
- vi. As regards the normal value in the case of UK, the petitioners have claimed the same on the basis of an evidence of domestic sale in UK. The petitioner has made adjustment on account of VAT and Inland freight for determination of normal value in UK. As regards normal value in Germany the petitioner has not been able to get any evidence of domestic sales in Germany. They have produced evidence of exports of subject goods by German producer to a third country. They have claimed the normal value based on the export price to the third country after making adjustments on account of inland freight. As regards Brazil and Bulgaria the petitioners have not been able to get evidence of domestic sales in these countries or any exports to third country. They have claimed normal value on the basis of constructed cost of production after taking the price of major raw material Acrylonitrile on the basis of internationally published prices.

- vii. The petitioners have claimed export price based on the published data of DGCI&S, Kolkata. The petitioners have made adjustments from the weighted average CIF export price on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland transportation in the country of export and port handling charges.
- viii. As per the petitioners, prior to this petition, the domestic industry was suffering from dumping of Acrylic Fibre from various countries and the Designated Authority has conducted investigations in respect of imports of Acrylic Fibre from USA, Thailand, Korea RP, Italy, Spain, Portugal, Japan, Mexico, Turkey and Taiwan. Evidently, the domestic industry has been suffering regularly due to dumping from various sources one after the another.
- ix. The exporters from UK, Germany, Brazil and Bulgaria are dumping Acrylic Fibre into India and the Designated Authority may examine the cumulative effect of these dumped imports from different sources as required under the Anti Dumping Rules.
- x. The quantum of imports from each of the subject country is more than the de-minimus limit.
- xi. Market share of imports from subject countries has increased.
- xii. Production, capacity utilization and sales of the domestic industry declined during the POI.
- xiii. The selling price of the domestic industry has increased during the POI. However, the industry has not been able to realize a fair price even after imposition of anti-dumping duty on imports from various sources as imports have started from newer sources.
- xiv. Sales volume of the domestic industry declined by more than 17% during 2000-01 which was directly due to shifting of some of the customers to the dumped imports.
- xv. Though there is no significant change in the employment level in the petitioner companies. However, should the situation continue, the domestic industry will have to restrict/close down production which would have significant adverse impact on employment.
- xvi. The sales of Acrylic Fibre at prices significantly below cost of production and fair selling price has resulted in heavy losses to the domestic industry. Continued dumping from one after other source has forced the domestic industry to sell the products at a price which does not permit recovery of even full cost of production.
- xvii. The injury to the domestic industry is directly being caused due to dumped imports from the subject countries

C EXPORTERS', IMPORTERS', USERS' AND OTHER INTERESTED PARTIES' VIEWS

4. Responses have been received from the following exporters and exporters' organization:

- i. Acordis UK Ltd., UK.
- ii. M/s. Lukoil Oil Company, Bulgaria.
- iii. DuPont Deutschland Holding GmbH & Co. KG, Germany.
- iv. Dralon GmbH – Bayerwerk, Germany.
- v. International Rayon and Synthetic Fibres Committee (CIRFS), Brussels.

5. The submissions made and/or the information provided by the above are as follows:

(i) Acordis UK Ltd., UK.

M/s. ACORDIS in their response, have offered price undertaking by confirming to undertake in consultation with the domestic Acrylic Fibre industry of India to not export Acrylic Fibre at a price which is injurious to the domestic industry.

(ii) M/s. Lukoil Company, Bulgaria.

M/s. Lukoil Company has furnished information regarding total quantity and value of exports to India, exports to other countries and domestic sales during the POI and in the years 1998 and 1999. As per the company the Acrylic Fibre was sold via a company registered in UK through an agent in India. The domestic market sales price include about 3% cost of financing since the terms of sale are usually with 90-120 days deferred payment and the normal interest rate around being 12% per annum. The exporter has not furnished complete response as per the prescribed questionnaire with Appendix 1 to 10.

(iii) DuPont Deutschland Holding GmbH & Co. KG, Germany

M/s. Dupont have informed that they are currently not producing and exporting Acrylic Fibre from Germany to India. Following a decision taken in June, 1990 the parent company and its affiliates have withdrawn from the production of Acrylic Fibre in the early 1990s. Therefore, they have not answered to the questionnaire.

(iv) Dralon GmbH – Bayerwerk, Germany

M/s. Dralon GmbH has informed that they are legal successor of Bayer Faser GmbH Business Unit Acrylic Fibres which was founded on January 1st 2001. The exports of their company during April 2000 – March, 2001 were 994 MT. During the preceding twelve month period the exports of their company were 1337 MT and so their business with India in volume terms has shrunk by 26% during the period of investigation. Compared to a mill consumption in India of approximately 1,20,000 T/annum their market share

was about 0.8% during the POI and with this market share they do not see any danger for the Indian domestic producers (as per de-minimis Rules). According to them the utilization rate of the Indian domestic Acrylic Fibre producers of around 93-94% during the period of investigation indicates the performance which is equal to or above the average of the world-wide industry. They requested that the anti-dumping complaint against Dralon should be cancelled as they consider it to be unfounded. However, they have not furnished complete information as required under Appendix 1 to 10 of the questionnaire sent to them.

(v) International Rayon and Synthetic Fibres Committee (CIRFS), Brussels

As per this association CIRFS is the representative association for the European man-made fibre industry. CIRFS has made the following major arguments in their communication sent through E-Mail:

- **Market Share**

The market share in India of imports from UK and Germany has remained at a very low level. In the case of Germany, market share (using the information in the Petition filed by the Forum of Acrylic Fibre Manufacturers) in 2000/2001 can be deduced as only 1.7%, and 1.1% in the case of the UK. It is the contention of CIRFS that, in the circumstances of the Indian acrylic fibres market, these market shares are too low to be the cause of injury to Indian producers.

- **Normal Value in UK and Germany**

The assessment of normal value in UK and Germany contained in the Petition is highly misleading. Information from specialist consultants shows estimates for selling prices in the West European market in April 2000 to March 2001 ranging from \$ 1.20 to \$ 1.45 per kg, with a weighted average of \$ 1.33. Assessment by the Petitioners of normal value in Germany as \$ 1.66 and \$ 2.67 in UK has thus clearly been made on the basis of specialist products, which are not comparable to those generally exported to India. The evidence in the consultants' report should thus be taken as the best evidence available of normal value in Germany, UK as the consultants concerned have an international reputation. However, the stated report of the consultant has not been received by the Authority.

As per CIRFS the true causes of injury to domestic industry are:

(a) Insufficient scale

The average size of the plants of the Petitioners ranges from 12,000 tonnes to 38,500 tonnes, with an average of 24,000 tonnes. This is well below the economic size needed to run efficient acrylic fibres production units.

In UK and Germany plant size varies from 70,000 tonnes to 150,000 tonnes. Some plants elsewhere in the world exceed 200,000 tonnes.

The Petitioners will continue to have serious problems unrelated to imports for as long as they continue to run units of uneconomic size.

(b) Inadequate technology

The Indian plants are in some cases old, some of them imported second-hand many years ago, and technologically obsolescent. This means that production costs are high, quality unreliable and that producers are unable to supply a full range of products.

(c) Excessive Protection of Acrylic Fibre Producers

The Indian textile industry (spinning, weaving, manufacture of finished apparel and household textiles) is both an essential supplier of products to the Indian population and a major export sector. It employs large numbers of people, and makes a very large contribution to India's export earnings. However, it has been seriously harmed by the imposition of anti-dumping duties, and will be further harmed if the current investigation results in the imposition of further anti-dumping duties.

CIRFS has further stated that:

i) Indian acrylic fibre prices are among the highest in the world

According to the leading firm of consultants the price of acrylic fibre in Asia in 2000/2001 averaged \$ 1.36 per kg. This is equivalent to approximately Rs 63. No specific information on selling prices in India in the same period is given in the Petition.

ii) Indian producers have increased prices faster than in other regions of the world

According to the Petition, selling prices of the Petitioners increased by 26.5% between 1999/2000 and 2000/2001. This is a much higher rate than in other regions of the world.

iii) The Indian textile industry will be denied access to better quality and more innovative fibres needed to increase the value added of their products

Producers in UK and Germany produce fibres to the highest quality standards, including many fibre variants not manufactured in India. These value added products will help Indian spinners, weavers and knitters increase the quality and attractiveness of their products, and the prices they can obtain on local and international markets, if they are permitted free access to them.

CIRFS has, therefore urged for immediate termination of the anti-dumping investigations concerning Germany and UK on the grounds of their incompatibility with the WTO Agreement and the serious damage which will

be caused to the Indian textile industry by further anti-dumping action on acrylic fibre.

6. The following importers/association have responded :

M/s. APM Industries Ltd., Bhiwadi, Rajasthan.
M/s. Deepak Spinners Ltd., Chandigarh.
M/s. Indian Spinners Association, Mumbai.

(i) M/s. APM Industries Ltd., Bhiwadi, Rajasthan

M/s. APM Industries Ltd. have given information relating to their imports from Italy and Japan which are not relevant to these investigations.

(ii) M/s. Deepak Spinners Ltd., Chandigarh

M/s. Deepak Spinners Ltd have given partial information to the questionnaire. In respect of imports from the subject countries they have given information about imports of *** quantity from Germany under Advance Licence (Duty exemption Scheme) @ *** CIF Mumbai. They have not shown any other imports of subject goods with payment of Duty in Annexure 4. They have also not furnished any information in respect of Annexure 5,6&7.

(iii) M/s. Indian Spinners Association, Mumbai.

Indian Spinners Association has in their response made the following major arguments:

(a) Insignificant imports from UK and Germany:

As per the Indian Spinners Association the figures of imports of Acrylic Fibre are as under:

(Quantity in kg.)

Year	U.K.	Germany	Brazil	Bulgaria
1996-97	55,624	10,14,658	Nil	Nil
1997-98	3,56,056	5,88,861	6,585	Nil
1998-99	18,521	8,56,765	25,334	Nil
1999-2000	9,404	9,76,966	70,213	18,070
2000-2001 (Apr. to Feb.)	94,074	11,11,224	Nil	18,519

Imports of acrylic fibre from the U.K. have come down substantially since 1997-98. The drop in import is of the order of 75%. In the case of Germany, there has been a small increase in imports, which is of the order of 8 to 9%. In the case of Brazil, there are no imports in the period of investigation. Bulgaria is not a regular supplier of the subject goods to India, and imports have taken

place only in the last two years, i.e. 1999-2000 and 2000-2001, and the level of imports is more or less the same. The above facts do not show any threat of increased imports from subject countries.

(b) Normal Value:

In the case of the U.K., the normal value has been worked out on the basis of one solitary sale document in the domestic market. An important issue like, normal value cannot be determined on the basis of one single transaction. A solitary transaction might be an unusual deal being for a small quantity or terms of trade in favour of the buyer might have influenced the transaction or there might have been an urgent and out-of-turn supply etc. It will therefore, be totally misleading to go by just one transaction to determine the normal value.

In the case of Germany, the price is determined on the basis of price in a single transaction of a producer from Germany exporting the subject goods to a third country. Here again it is necessary to go into the levels of trade, quantities involved and conditions and terms of sale. It is also necessary to find out whether the third country is an appropriate country to consider the price. More importantly, a single transaction may be a freak deal.

The costing route adopted in the case of Brazil and Bulgaria raise the question of the assumptions made in the determination of cost of production, and their justification. Since the assumptions have not been given, it is not possible to comment on the same.

(c) Evidence of Injury:

- The figures of country-wise imports given in the petition do not appear to be correct as they appear to be at variance with DGCIS data for April, 2000 to February, 2001. The correct figures should be as given in para 6(iii)(a) above.
- So far as production and capacity utilization are concerned, here again data given by the petitioner has been distorted by referring to only three petitioners and leaving out supporting producers. If the total production of the industry as a whole is taken, then the picture is as under:-

<u>Year</u>	<u>Production of Acrylic Fibre (Quantity in tons)</u>
1998 - 1999	78,917
1999 - 2000	79,313
2000 - 2001	94,704

- It would thus be seen that in the year of investigation, domestic production of acrylic fibre has increased by 20% over the previous year.

- So far as the market share is concerned the correct picture is as under:-

Year	Market Share			
	Production in Tonns	Imports from 4 countries in Tonns	Total	Imports to Total as %
1999-2000	79,313	1075	80,388	1.34
2000-2001	94,704	1224	95,928	1.27

- It will be seen from the above that the Market Share of domestic producers has increased, while that of imports has gone down.
- The price of Acrylic fibre vis-à-vis that of Acrylonitrile, the main raw material depict the following position:-

Year	Price Per Kg.	
	Acrylic	Acrylonitrile
1999 - 2000	74	31
2000 - 2001	90	42

- While the raw material cost increased by Rs.11 per kg., the selling price increased by an hefty Rs.16 per kg.
- Profitability depends upon various factors like Managerial efficiency, productivity, level of technology, upkeep of machines level of rationalization, industrial relations etc. Hence losses suffered by the domestic producers, if any, cannot be said to have increased because of imports. The petitioners have also not given information on many parameters as required statutorily.

(d) Causal Link

The information on causal link is not proper and to the point and the domestic producers have failed to establish the causal link. Thus the petitioners have failed to establish any dumping or injury or causal link. There is therefore no justification to proceed with the investigation and the finding may be given to say that there has been no dumping and no ground for imposition of anti-dumping duty.

D. EXAMINATION AND FINDINGS BY THE AUTHORITY

7. The submission made by the petitioners, importers, exporters and other interested parties, to the extent filed before the Authority have

been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter.

8. The Authority confirms, in the absence of complete and sufficient response from the exporters from subject countries in the form and manner prescribed, having made the findings with regard to exports from subject countries on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra.
9. The cases of new exporters or those stated to be willing to give price undertaking shall be considered, on request, by the Authority in accordance with the Rules supra.

Product Under Consideration And Like Article

10. The product under consideration in this investigation is Acrylic Fibre. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units. Acrylic fibre can be acrylic staple fibre, acrylic tow or acrylic top. All the three forms are the subject matter of this investigation. Acrylic Fibre is produced in various grades, which are defined in terms of its Denier. Acrylic Fibre finds application in apparel, household and industrial areas. Acrylic Fibre is classified in chapter heading 55.01 and 55.03. The product is classified under 5501.30 and 5503.30 under the Customs Tariff Act at six digit levels and under 5501.3000 and 5503.3000 under ITC. The present investigations are in respect of the product under consideration irrespective of the classification under which they are imported. Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
11. The petitioner claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. None of the interested parties who have responded to the investigation has disputed that Acrylic Fibre exported by the subject countries and Acrylic Fibre produced by the domestic industry are like article. Thus, the Authority holds, for the purpose of preliminary determination, that Acrylic Fibre being produced by the domestic industry is like article to the product under consideration.

De-Minimus Limits

12. As regards ascertaining that the imports from the subject countries during the period of investigation (POI) are above de-minimus levels, the Authority has referred to the DGCI&S published data. As per the data of DGCI&S the imports of Acrylic Fibre during POI under the classification 55013000 'Synthetic Filament Tow, Acrylic/Mod-Acrylic' and 55033000 'Staple Fibres of Acrylic/Mod-Acrylic' are as under:

Country Name	Quantity (MT)	%age share in imports
Brazil	665.51	4.765
Bulgaria	540.29	3.868
Germany	1782.94	12.765
UK	1206.36	8.637

Thus, the Authority finds that the imports from the subject countries during the POI are above de-minimus levels. The Authority does not find the contention of Indian Spinners Association as correct that there are no imports of Acrylic Fibre from Brazil during POI. The Initiation Notification dated 28th August, 2001 had clearly mentioned that Acrylic Fibre can be Acrylic Staple Fibre, Acrylic Tow or Acrylic Top.

Domestic Industry

13. The petition has been filed by Forum of Acrylic Fiber Manufacturers, New Delhi on behalf of the domestic industry. The following producers of acrylic Fibre in India have specifically consented to participate in the present Anti-dumping investigations.

- (a) Indian Acrylics Limited,
- (b) Consolidated Fiber and Chemicals Limited,
- (c) Pasupati Acrylon Limited,

The above-mentioned companies have provided all information required for the purpose of the present investigation and have offered themselves for further information and verification. These companies account for a major proportion of the total Indian production of subject goods. None of the responding interested party has raised any point regarding the standing of the petitioners. Thus, the Authority holds that petitioners satisfy the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra, for the purpose of preliminary finding. The Authority also considers these petitioner companies as 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) supra.

E. DUMPING & EXAMINATION OF CLAIMS MADE ON NORMAL VALUE & EXPORT PRICES

Normal Value

14. Under Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 normal value in relation to an article means:

“(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)";

15. The Authority sent questionnaire to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). The Authority received responses from the following exporters and exporters association.

- i. Acordis UK Ltd., UK.
- ii. M/s. Lukoil Oil Company, Bulgaria.
- iii. DuPont Deutschland Holding GmbH & Co. KG, Germany.
- iv. Dralon GmbH – Bayerwerk, Germany.
- v. International Rayon and Synthetic Fibres Committee (CIRFS), Brussels.

However, the responses filed by the exporters are found to be grossly insufficient and incomplete for the purpose of preliminary finding, as discussed in detail hereinbelow.

Normal value determination for UK

16. The Authority notes that none of the exporters from UK has filed complete response. Only M/s. Acordis, UK has responded and has offered price undertaking. They have not given full information as required under Appendix 1 to 10 and part A to H of the questionnaire. *As per Rule 15(2) "No undertaking as regards price increase under clause (ii) of the sub-rule (1) shall be accepted from any exporter unless the Designated Authority had made preliminary determination of dumping and the injury".* Therefore, it is incumbent upon the Authority to make preliminary determination of dumping and injury. As no information about domestic sales price structure of the subject goods in UK, its cost of production and other information as per the questionnaire has been furnished, the Authority has proceeded to rely upon the best available information for determination of normal value. The petitioners have claimed normal value in respect of UK on the basis of an evidence of domestic sales in UK based on a solitary sales invoice. Indian

Spinners Association has stated that normal value cannot be determined on the basis of one single transaction as it may not be a truly representative transaction.

17. As per International Rayon and Synthetic Fibres Committee (CIRFS), Brussels the assessment of normal value in UK contained in the petition is highly misleading. The normal value of dollar 2.67 in the case of UK as claimed in the petition is made on the basis of specialty products. The Authority finds that none of the exporters have given complete and sufficient information to enable it to determine the normal value based on the domestic sales price. As per the Anti Dumping Rules Annexure 1(2) sales of the like product in the domestic market of the exporting country have to be in the ordinary course of trade. The Authority is not able to accept the view of CIRFS unless such a claim is supported by full information as required in the questionnaire. The Authority confirms, in the absence of complete and sufficient response from the exporters from subject countries in the form and manner prescribed, having made the findings with regard to exports from subject countries on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra. Accordingly, the Authority has considered the evidence as furnished by the petitioner for normal value determination, i.e. as per the domestic sales transaction as furnished by the petitioner. The normal value so determined for UK is US\$ ***

Normal value determination for Germany:

18. Only M/s. Dupont and M/s. Dralon have responded from amongst the exporters of Germany. M/s. Dupont have informed to have not exported Acrylic Fibre to India as they have withdrawn from production of Acrylic Fibre in early 1990s. M/s. Dralon, who are legal successor of M/s. Bayer Faser GmbH, have exported 994 MT to India during POI. They have given information about previous years export and that their business with India has shrunk by 26% during POI. However, they have not given complete information as required under Appendix 1 to 10 and part A to H of the questionnaire. As per Indian Spinners Association the single transaction of export from Germany to a third country may not be sufficient to know the level of trade, quantities involved and conditions and terms of sales. According to CIRFS, the normal value in Germany of dollar 1.66 in the petition is made on the basis of special products which are not comparable to the products generally exported to India. The Authority reiterates that as per the Anti Dumping Rules Annexure 1(2) sales of the like product in the domestic market of the exporting country have to be in the ordinary course of trade. The Authority is prevented to accept the view of CIRFS and Indian Spinners Association unless such a claim is supported by full information as required in the questionnaire. The Authority confirms, in the absence of complete and sufficient response from the exporters from subject country in the form and manner prescribed, having made the findings with regard to exports from subject countries on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra. Accordingly, the Authority has considered the evidence as furnished by the petitioner for normal value determination, i.e. as per the evidence of exports

from Germany to a third country as furnished by the petitioner. The normal value so determined for Germany is US\$ ***

Normal value determination in respect of Bulgaria:

19. M/s. Lukoil Company has given information about total quantity and value of exports to India, exports to other countries and domestic sales. Average unit price has also been given. However, the information as required in Appendix 1 to 10 and part A to H of the questionnaire has not been furnished. The Authority finds that the information is grossly insufficient and incomplete. The Authority is prevented from accepting the information furnished by the exporter from Bulgaria in view of its being insufficient and incomplete as according to the Anti Dumping Rules Annexure 1(2) sales of the like product in the domestic market of the exporting country have to be in the ordinary course of trade. The Authority confirms, in the absence of complete and sufficient response from the exporters from subject country in the form and manner prescribed, having made the findings with regard to exports from subject country on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra. Accordingly, the Authority has considered the available information as furnished by the petitioner for normal value determination, i.e. as per the constructed cost of production of subject goods. The normal value so determined for Bulgaria is US\$ ***

Normal value determination for Brazil:

20. None of the exporters from Brazil has responded to the questionnaire. The domestic industry has claimed normal value in respect of Brazil on the basis of constructed cost of production. They have considered the price of major raw material Acrylonitrile on the basis of published price of this item in leading journal. Accordingly, the normal value so constructed is US\$ *** in respect of Brazil.

Export price in respect of UK and Germany:

21. None of the exporters from UK and Germany has cooperated in furnishing the export price. The petitioners have determined export price on the basis of DGCI&S published data. The DGCI&S published data is available for the period April 2000 – March 2001. The imports of Acrylic Fibre are shown in the data under the classification 55013000 'Synthetic Filament Tow, Acrylic/Mod-Acrylic' and 55033000 'Staple Fibres of Acrylic/Mod-Acrylic'. The Authority has considered the export price in respect of UK and Germany based on this data. The petitioner has shown adjustments on account of ocean freight, insurance, commission, inland transportation and port handling charges. The Authority has allowed adjustments of \$*** on account of ocean freight @ \$50/MT, insurance .5% of CIF, commission 2% of CIF, inland freight 2% of FOB and port charges 2% of CIF. The ex-factory export price comes to US\$*** for UK. After allowing similar adjustments the export price at ex-factory level in respect of Germany comes to US\$ ***.

Export price in respect of Bulgaria:

22. M/s. Lukoil Company, Bulgaria has responded to the questionnaire but has given insufficient and incomplete information. They have not given transaction-wise details of exports made to India in the form given in Appendix- 2. Instead they have given total export sales, total exports to other countries and total domestic sales along with respective unit price. The Authority finds the information as insufficient and incomplete. It is however seen that the exporter has shown exports of 868 MT during POI. Price shown in the response are stated to be FCA Bourgas delivery and advance payment terms. In absence of clear and complete information about the CIF export price to India and other information as per the questionnaire the Authority could not consider even this limited information about the export quantity and export price as furnished by the exporter. The Authority therefore relied upon the DGCI&S data for determining the export price which comes to dollar *** CIF. After making adjustment of dollar *** on account of ocean freight @ \$50/MT, insurance 0.5% of CIF, commission 2% of CIF, inland freight 2% of FOB and port charges 2% of CIF, the export price at ex-factory level comes to dollar ***.

Export price for Brazil:

23. There has been no response from any exporter from Brazil. The Authority has therefore relied upon the DGCI&S data for export price determination. As per this information the weighted average CIF export price comes to US\$ ***. Adjustments have been made on account of ocean freight @ \$50/MT, insurance 0.5% of CIF, commission 2% of CIF, inland freight 2% of FOB and port charges 2% of CIF. The export price at ex-factory level comes to US\$***.

Dumping margin

24. Considering the normal value and export price, determined as detailed above, the dumping margin comes as under:

S. No.	Country	Dumping Margin %
1.	UK	80.80 %
2.	Germany	10.51%
3.	Bulgaria	51.11%
4.	Brazil	229.72%

F. INJURY

25. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:

“Determination of Injury:

- (i) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that

import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;

- (ii) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules."

26. The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti- Dumping Rules lay down that:

- a. A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.
- b. While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

27. Views of the petitioners

- (i) The domestic industry was suffering from dumping of Acrylic Fibre from various countries and the Designated Authority has conducted investigations in respect of imports of Acrylic Fibre from USA, Thailand, Korea RP, Italy, Spain, Portugal, Japan, Mexico, Turkey and Taiwan. Evidently, the domestic industry has been suffering regularly due to dumping from various sources one after the another.
- (ii) The exporters from UK, Germany, Brazil and Bulgaria are dumping Acrylic Fibre into India and the

- Designated Authority may examine the cumulative effect of these dumped imports from different sources as required under the Anti Dumping Rules.
- (iii) The quantum of imports from each of the subject country is more than the de-minimus limit.
 - (iv) Market share of imports from subject countries has increased.
 - (v) Production, capacity utilization and sales of the domestic industry declined during the POI.
 - (vi) The selling price of the domestic industry has increased during the POI. However, the industry has not been able to realize a fair price even after imposition of anti-dumping duty on imports from various sources as imports have started from newer sources.
 - (vii) Sales volume of the domestic industry declined by more than 17% during 2000-01 which was directly due to shifting of some of the customers to the dumped imports.
 - (viii) Though there is no significant change in the employment level in the petitioner companies. However, should the situation continue, the domestic industry will have to restrict/close down production which would have significant adverse impact on employment.
 - (ix) The sales of Acrylic Fibre at prices significantly below cost of production and fair selling price has resulted in heavy losses to the domestic industry. Continued dumping from one after other source has forced the domestic industry to sell the products at a price which does not permit recovery of even full cost of production.
 - (x) The injury to the domestic industry is directly being caused due to dumped imports from the subject countries

28. Views of exporters and importers:

(i) As per Indian Spinners Association:

Imports of acrylic fibre from the U.K. have come down substantially since 1997-98. The drop in import is of the order of 75%. In the case of Germany, there has been a small increase in imports, which is of the order of 8 to 9%. In the case of Brazil, there are no imports in the period of investigation. Bulgaria is not a regular supplier of the subject goods to India, and imports have taken place only in the last two years, i.e. 1999-2000 and 2000-2001, and the level of imports is more or less the same. The above facts do not show any threat of increased imports from subject countries.

- In the year of investigation, domestic production of acrylic fibre has increased by 20% over the previous year.
- The Market Share of domestic producers has increased, while that of imports has gone down.
- While the raw material cost increased by Rs.11 per kg., the selling price increased by an hefty Rs.16 per kg.
- Profitability depends upon various factors like Managerial efficiency, productivity, level of technology, upkeep of machines level of rationalization, industrial relations etc. Hence losses suffered by the domestic producers, if any, cannot be said to have increased because of imports.

(ii) As per M/s. Dralon GmbH, Germany compared to a mill consumption in India of approximately 1,20,000 T/annum their market share was about 0.8% during the POI and with this market share they do not see any danger for the Indian domestic producers (as per de-minimus Rules). According to them the utilization rate of the Indian domestic Acrylic Fibre producers of around 93-94% during the period of investigation indicates the performance which is equal to or above the average of the world-wide industry.

(iii) As per CIRFS:

The market share in India of imports from UK and Germany has remained at a very low level. In the case of Germany, market share in 2000/2001 can be deduced as only 1.7%, and 1.1% in the case of the UK. These market shares are too low to be the cause of injury to Indian producers and according to them the true causes of injury to domestic industry are:

(a) Insufficient scale

The average size of the plants of the Petitioners ranges from 12,000 tonnes to 38,500 tonnes, with an average of 24,000 tonnes. This is well below the economic size needed to run efficient acrylic fibres production units. In UK and Germany plant size varies from 70,000 tonnes to 150,000 tonnes. Some plants elsewhere in the world exceed 200,000 tonnes. The Petitioners will continue to have serious problems unrelated to imports for as long as they continue to run units of uneconomic size.

(b) Inadequate technology

The Indian plants are in some cases old, some of them imported second-hand many years ago, and technologically obsolescent. This means that production costs are high, quality unreliable and that producers are unable to supply a full range of products.

(c) The damage caused to Indian Textile Production is by excessive protection of acrylic fibre producers

Examination by the Authority:

29. The Authority has examined the information regarding the volume of exports from the subject country during the period of investigation and the preceding years. During the POI the imports from the four subject countries taken together were of 4195 MT. During the year 1999-2000 these imports were 2469 MT and 3739 MT during 1998-99 (as per DGCIS data). These imports account for a market share of 3.35% in 1998-99, 2.18% in 1999-2000 and 3.73% during 2000-01. When compared to the previous year 1999-2000 the share in the market had shown an appreciable increase during the POI. However, in volume terms the imports from the subject countries during POI showed an increase of 69% over the imports in the previous year. The increase in market share though not very significant is however appreciable and the increase in imports in absolute terms does hold a threat for the domestic industry. The Authority has found that there has been an increase in the dumped imports in absolute terms.

30. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree. The Authority has compared the landed value of imports of subject goods from subject countries during the POI with the net sales realization and has found that there has been a significant price undercutting by the dumped imports. The landed value of imports has been found to be significantly lower than the domestic industry's net sales realization. The imports were having significantly suppressing/ depressing effect on the prices in the domestic market, as the domestic industry has not been able to raise its selling price in view of the dumped imports.

31. For the examination of the impact on the domestic industry in India, the Authority also considered such further indices having a bearing on the state of industry as capacity utilization, production, sales, net sales realization profitability, etc. The Authority found that:

- (a) The selling price of the domestic industry is significantly below the price which would have permitted the domestic industry a fair recovery of its cost of production and earn a reasonable return.
- (b) The installed capacity of the three petitioner companies had increased during the POI. However, the total production of the petitioner companies declined during the POI in comparison to the previous year. The production of the two other domestic producers mentioned in Para 2 (ii) earlier, who have supported the petition but have not participated in the present investigation, may have increased during the POI. The argument of the Indian Spinners Association is that the production of Acrylic Fibre has increased during POI. The petitioner companies account for 61% share, i.e. a major proportion of the domestic production of the subject goods during the POI and have been construed as 'Domestic Industry' in

terms of Rule 2(b) supra and so stated in foregoing Para 13 of these findings. Therefore, the Authority holds the view that the domestic industry has suffered injury on account of decline in production and capacity utilization. The sales volumes of the domestic industry as represented by the petitioner companies also declined during the POI by 16.25% in comparison to the previous year.

- (c) Though selling prices increased in the investigation period as compared to the previous years, the increase in the Cost of production was much more than the increase in the selling prices. In fact, it is found that the loss per unit has significantly increased in the investigation period. Thus, the dumped imports have prevented the domestic industry from effecting legitimate price increase to realize a reasonable price. The industry has suffered material injury on account of depressed selling prices resulting in non-recovery of cost of production and thereby suffering financial losses.

Cumulative assessment of injury

32. As per annexure-II (iii), in cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti-dumping investigation, the Authority is required to cumulatively assess effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% of the imports of like article --- and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article. The Authority has found that the margin of dumping in respect of each of the subject country is more than 2% and the volume of imports from each country is also more than 3%. The Authority has also found it appropriate to cumulatively assess the effect of imports of the subject goods on the domestically produced like article and has found that there is a cumulative effect of injury by imports of subject goods on the domestic industry.

G. CAUSAL LINK

33. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry the principle (iv) of Annexure-II of the Anti-Dumping Rules states:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic Industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

Views of the Petitioners:

34. The petitioners have stated that injury to the industry has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries. As the landed value of the subject goods is significantly below the selling price of the domestic industry, the industry has been forced to keep its selling price significantly below the cost of production. Therefore, the industry has not been able to realize a non-injurious price. The price suppression suffered due to dumped imports has resulted in severe financial losses to the domestic industry. The industry has also been prevented from increasing its sales and production. The domestic industry has also stated that there has not been a contraction of demand of the subject goods and the injury to the industry cannot be attributed to any fall in demand.

Examination and Findings of the Authority:

35. The Authority has also considered the views expressed by the Indian Spinners Association and CIRFS as regards the causal link, which have been mentioned, in the preceding paragraphs. The Authority, in its views, does not find the reasons adduced by the said interested parties attributable to the injury to the domestic industry in the present investigation. For the examination of the impact on the domestic industry in India, the Authority considered such indices having a bearing on the state of industry as production, sales, market share, profitability, net sales realisation etc. in accordance with Annexure-II (iv) of the Rules supra. The Authority has also found that the demand for the subject goods during the period of investigation (POI) has remained almost same as compared with the demand in the preceding year 1999-2000.

36. After examining the various economic parameters as above the Authority has come to the following conclusions:

- i) The capacity utilization of the domestic industry has declined and the domestic industry has been prevented from utilization of higher capacity due to dumped imports.
- ii) The market share of the dumped imports from the subject countries has increased.
- iii) Sales of the domestic industry have declined during the POI.
- iv) The selling price of the domestic industry increased during the POI as compared to year 1999-2000. However, the same has been below the non-injurious price (NIP) on account of dumped imports.
- v) The industry has suffered financial losses due to price undercutting of dumped imports.

- vi) The domestic industry has suffered due to price suppression. They have not been able to raise their selling price to recover the cost of production, as the landed value of the dumped imports has been significantly lower than the cost of production.
- vii) The above economic parameters cumulatively and collectively establish that domestic industry has suffered material injury on account of dumping.

H. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

37. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country.

38. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

I. CONCLUSIONS

39. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (i) Acrylic Fibre has been exported to India from subject countries below its normal value;
- (ii) The domestic industry has suffered material injury;
- (iii) The material injury has been caused by the dumped imports from subject countries;

40. The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty provisionally, pending final determination, on all imports of Acrylic Fibre from subject countries in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority proposes to recommend the amount of anti dumping duty not exceeding the margin of dumping or the margin of injury whichever is

lesser and which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports is proposed to be compared with the non injurious selling price of the petitioner companies determined for the period of investigation.

41. Accordingly, the Authority recommends that provisional anti dumping duties be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of Acrylic Fibre falling under Chapter 55 of Schedule I of Custom Tariff Classification originating in or exported from UK, Germany, Bulgaria and Brazil pending final determination. The anti dumping duty shall be as in column 3 in the following table.

S. No. (1)	Country (2)	Anti Dumping Duty (US \$ per Kg) (3)
1.	All producers/exporters from UK	0.684
2.	All producers/exporters from Germany	0.143
3.	All producers/exporters from Bulgaria	0.619
4.	All producers/exporters from Brazil	1.275

42. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

J. FURTHER PROCEDURE

43. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:-

- (a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- (b) Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of these preliminary findings. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;
- (c) The Authority would provide opportunity to all the interested parties for making oral submissions which have to be rendered thereafter in writing;

- (d) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;
- (e) The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority